राष्ट्रीय सेमिनार

मदरसों की इब्तिदायी तालीम के निसाब में यक्सानियत

Uniformity in Primary Level Curriculum in Madarsa Education

21 नवम्बर, 2009, स्थान–लखनऊ

REPORT

नालंदा

NALANDA
Seminar Report on
Uniformity in Primary Level Curriculum in Madarsa Education
'मदरसों की इब्तिदायी तालीम के निसाब में यक्सानियत'
21 नवंबर, 2009
सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ

'हालिया सालों में मदरसों ने मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों के मुकाबले जनता का ज्यादा ध्यान खींचा है। हो सकता है, इसके पीछे दूसरे मजहबों के आम लोगों की यह समझ हो कि कट्टरपन, इस्लामवाद और अतिवादी हिंसा मदरसों की वजह से है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिये मदरसा षिक्षा के आधुनिकीकरण पर बहस चलाने तथा मदरसा षिक्षा, उससे निकलने वाले छात्रों और उनकी जिन्दगी की गुणवत्ता को व्यापक नजरिये से देखने की जरूरत है।

मदरसा षिक्षा की शुरुआत से ही एक पाठयक्रम चला आ रहा है जिसमें बहुत कम बदलाव हुये हैं। आज लाखों मुस्लिम बच्चे, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे अपनी प्राथमिक और शायद एकमात्र औपचारिक षिक्षा इन मदरसों से प्राप्त कर रहे हैं। यहां केवल साहित्य, इस्लामी अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की थोड़ी जानकारी दी जाती है। यह न केवल माता–पिता बल्कि षिक्षा से किसी प्रकार से जुड़े हर व्यक्ति की चिन्ता होनी चाहिये। आजकल रोजगार देने वालों की मांगों के अनुसार मदरसा छात्रों को मिलने वाली षिक्षा में बदलाव किये जाने चाहिये। इसे अब और टाला नहीं जा सकता है। यह काम मदरसों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में बिना कोई कमी किये पूरी तरह संभव है।' यह बात जामिया मिलिया इस्लामिया के डा. जसीम अहमद ने 'नालन्दा' द्वारा आयोजित सेमिनार में पेष अपने पर्चे में कही।

मकतब–मदरसा षिक्षा में सुधार के लिए कई साल से काम कर सही संस्था 'नालन्दा' ने 'मदरसों की इब्तिदाई तालीम के निसाब में यकसानियत' (मदरसों में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की समानता) विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 21 नवंबर, 2009 को सहभागी षिक्षण केन्द्र, लखनऊ में किया। सेमिनार में दो सत्रों में वक्ताओं ने अपने पर्चे प्रस्तुत किये। पहले सत्र में

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में वरिष्ठ लेक्चरर डा. मुजम्मिल हुसैन कासमी ने 'मदरसा षिक्षा में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में सुधार' विषय पर अपना पर्चा पेष किया। डा. कासमी का मदरसा षिक्षा सुधार में अग्रणी योगदान है। जामिया मिलिया के ही डा. जसीम अहमद ने 'मदरसा में प्रारम्भिक पाठ्यक्रमीय क्षमतायें पहचानना, रचनात्मकता बढ़ाना व जीवन की नई दिषा तय करना' शीर्षक से अपना आलेख रखा। इसी सत्र में विक्रमषिला एजुकेषन रिसोर्स सोसायटी, कोलकाता से पधारी डा. मधुमिता ने पष्चिम बंगाल में मदरसा षिक्षा पर अपने अनुभवों को समेटते हुए 'मदरसों के प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एकरूपता' पर अपना पर्चा पेष किया। इस सत्र की अध्यक्षता सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई की सुश्री रत्ना माथुर ने की। सत्र के अंत में प्रतिभागियों ने सवाल पूछे जिनके जवाब वक्ताओं व सत्र अध्यक्ष ने दिये। दोपहर के भोजन के बाद दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डा. मुज्जमिल हुसैन कासमी ने की। इस सत्र में दिल्ली विष्वविद्यालय के डा. नईमुल हसन ने 'मदरसा पाठ्यक्रम और आधुनिक युग की मांग' पर अपना आलेख पढ़ा। सत्र में लखनऊ के प्रख्यात लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री शकील सिद्धीकी ने 'मुष्किलों के बीच निसाब की यकसानियत' विषय पर हिन्दी में अपना आलेख प्रस्तुत किया। इसी सत्र में गुजरात से पधारे पी. टी. सी. कालेज, भावनगर के डा. हाजीभाई बादी ने 'गुजरात में प्राथमिक मदरसा पाठ्यक्रम' पर अपना पर्चा पेष किया। सत्र के अन्त में खुला सत्र रखा गया जिसमें प्रतिभागियों के सवालों का जवाब दोनों सत्रों के वक्ताओं ने दिया। इसके अलावा प्रतिभागियों ने भविष्य में कामकाज के अनेक मूल्यवान सुझाव भी दिये।

सेमिनार में विषिष्ट विद्वानों के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, मदरसों तथा नालन्दा मदरसा षिक्षा कार्यक्रम से जुड़े लगभग 65 प्रतिभागियों ने बड़े जोषोखरोष से हिस्सा लिया। स्वयंसेवी संस्थाओं में ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज़, बेटी फाउंडेषन, लोकभारती, शाष्वत सहकारी संस्थान, सहारा वेलफेयर फाउंडेषन, विक्रमषिला एजुकेषन रिसोर्स सोसायटी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, आक्सफैम, प्रयत्न फाउंडेषन, प्रोएक्ट, आदि तथा मदरसा मोइनुल इस्लाम, मदरसा मदीनतुल उलूम, मदरसा दारुल उलूम, मदरसा अमीनुल कुरान, मदरसा रहमानिया, किंग जार्ज इंटर आदि कालेज के प्रतिनिधि शामिल थे। सेमिनार का संचालन नालन्दा में मदरसा षिक्षा कार्यक्रम के संयोजक एवं टीम लीडर मो0 आसिम सिद्दीकी ने किया। नालन्दा में मदरसा षिक्षा कार्यक्रम के उप–संयोजक मो0 हिदायतुल्ला, मदरसा कार्यक्रम के फील्ड स्टाफ व संस्था के अन्य कर्मचारियों ने सेमिनार के संचालन व प्रतिभागियों को सुविधायें दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

नालन्दा के प्रयास

सेमिनार के आरंभ में नालन्दा के कार्यकारी निदेषक श्री प्रभात झा ने विषिष्ट अतिथियों व सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने नालन्दा के कार्यों का उल्लेख करते हुए सेमिनार के उद्देष्यों पर प्रकाष डाला। श्री झा ने बताया कि गैर–सरकारी संस्था, 'नालन्दा' की स्थापना 1996 में प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों, खासकर गरीब तबके के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण षिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से की गई थी। संस्था 6–7 साल से मकतब–मदरसा षिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अरबी–फारसी मदरसा बोर्ड, उत्तर प्रदेष के अनुसार प्रदेष में लगभग 7000 मदरसे हैं जिनमें लगभग 1300 मान्यता प्राप्त हैं। प्रदेष सरकार द्वारा केवल 360 मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है जबकि बाकी सभी समुदाय के सहयोग से चलते हैं। सरकार 6–14 साल के सभी बच्चों को षिक्षा उपलब्ध कराने हेतु चलाये जाने वाले सर्व षिक्षा अभियान के अंतर्गत 'मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' द्वारा मदरसों को आधुनिक षिक्षा की परिधि में लाने की कोषिष कर रही है। श्री झा ने कहा कि नालन्दा ने मदरसों में दीनी तालीम के साथ दुनियाबी तालीम को शामिल कराने की बहुत कोषिषें की हैं जिनके नतीजे भी निकले हैं। खुषी की बात है कि बदलते समय की आवष्यकताओं को समझते हुए आज ज्यादातर मदरसे दीनी तालीम के साथ दुनियाबी तालीम पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ बहुत छोटे मदरसे ही ऐसे बचे हैं जहां केवल दीनी तालीम दी जा रही है। हालांकि दुनियाबी विषयों जैसे हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, आदि को भी मुदर्रिस दीनी विषयों की तरह ही पढ़ाते हैं। इससे जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा नहीं मिल पाती है वही इन विषयों पर उनका ध्यान भी कम रहता है। कुछ मदरसे सरकारी पाठ्यक्रम (निसाब) पर चलते हैं जबकि बाकी के अलग–अलग पाठ्यक्रम हैं। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में बाल केन्द्रित षिक्षण पद्धतियों को अनदेखा किया गया है। कुछ जगह बाजार की किताबों को ही पाठ्यक्रम मान कर पढ़ाया जा रहा है। मदरसों में अंग्रेजी के चलन में भी भिन्नता है तथा बच्चों पर भाषायें सीखने का दबाव भी है। इन सारी वजहों से बच्चों की दक्षताओं में भारी अन्तर है और षिक्षा की गुणवत्ता सुनिष्चित करने में दिक्कत आती है। इसके लिए मदरसों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाना जरूरी है। हालांकि पाठ्यक्रमों में बदलाव की कोषिषें जारी हैं, पर इस मामले में काफी गलतफहमी और असमंजस की स्थिति है। जहां बहुत से लोगों को सरकार द्वारा दीनी तालीम में दखलंदाजी का डर सता रहा है वहीं अलग–अलग इस्लामी मसलक भी मदरसा षिक्षा पर अपनी खास छाप छोड़ना चाहते हैं। आज अगर मानक पाठ्यक्रम सभी मदरसों में लागू न हुआ तो मदरसों के बच्चे पीछे छूट जांयेगे। इस दिषा में बहुत सी संस्थायें काम कर रही हैं और देष के कई राज्यों में काफी काम हुआ है। इन प्रयासों और अनुभवों का साझा करने के लिए ही नालन्दा ने यह सेमिनार आयोजित किया है। सेमिनार के माध्यम से इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं, विषेषज्ञों, मदरसा षिक्षकों तथा मदरसों के इंतजामिया के बीच एक नेटवर्क बनाने के प्रयास भी किये जाने चाहिये। नालन्दा, मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतब–मदरसों में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की ओर सरकार का भी ध्यान खींचना चाहती है। इसके पहले 'नालन्दा' 30 अगस्त, 2008 को 'मकतब–मदरसा में प्राथमिक षिक्षा के सुदृढ़ीकरण' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार और कई क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन कर चुकी है। नालन्दा ने बच्चों के लिए षिक्षण सामग्री व मदरसा षिक्षकों के प्रषिक्षण हेतु सामग्री भी तैयार की है।

श्री प्रभात झा के स्वागत भाषण के बाद नालन्दा में मदरसा षिक्षा कार्यक्रम के संयोजक श्री आसिम सिद्दीकी ने प्रतिभागियों को नालन्दा द्वारा किये गए प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी दी। नालन्दा, मुस्लिम समुदाय को प्राथमिक षिक्षा की जरूरत के प्रति जागरूक करते हुए मकतब–मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण षिक्षा दिलाने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने में अपनी भूमिका अदा करती रही है। नालन्दा ने बाराबंकी, सीतापुर एव बहराइच जिलों के 19 ब्लाकों के 324 मकतब–मदरसों तक अपनी पहुंच बनाई है। 33 क्लस्टर बना कर उसने 1767 षिक्षकों को प्रषिक्षण दिया तथा प्रषिक्षण माड्यूल 'आगाज़' व 'तष्कील' तैयार किये व 'परवाज़' का नया संषोधित संस्करण निकाला। मदरसों में गहन रूप से काम करने के लिए 20 मदरसे चुने गये। इन मदरसों के लिए संदर्भ समूह विकसित करने के प्रयास जारी है जिसमें 18 व्यक्तियों का चयन कर उनकी क्षमतायें बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। विषेषज्ञ के रूप में तैयार करने के लिए इनको तीन चरणों का प्रषिक्षण दिया गया। संदर्भ समूह विकास के लिए 'हमकदम–1', 'हमकदम–2' व 'हमकदम–3' प्रषिक्षण माड्यूल तैयार किये गये। नालन्दा ने बच्चों के लिए अच्छी किताबें प्रकाषित की हैं जिनमें कक्षा 1 व 2 के लिए उर्दू भाषा व हिसाब की 'अपनी किताब' व उर्दू में 5 चित्रात्मक कहानी पुस्तकें शामिल हैं। मदरसों के बच्चों में पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए भी नालन्दा प्रयास करती रहती है। इस दिषा में 500 बच्चों के साथ रचनात्मक लेखन कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी जुबान और चित्रों के माध्यम से अपने परिवेष को सबके सामने रखा है। इस प्रयास में विभिन्न मदरसों के बच्चों ने 30 बाल पत्रिकाओं का निर्माण किया। मदरसों की आवष्यकतायें समझने के लिए एक अध्ययन किया गया तथा दूसरे राज्यों में चल रहे काम को देखने के लिए संदर्भ समूह एवं मदरसा षिक्षा कार्यक्रम से जुड़े 30 सदस्य विक्रमषिला, कोलकाता एवं सार्ड, भरतपुर के मदरसा कार्यक्रम देखने गये। श्री आसिम सिद्दीकी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि मदरसे अपनी शैक्षिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, पर अषिक्षा और संकुचित विचार इसमें बड़ी बाधा हैं।

पाठ्यक्रम सुधार के अनुभव

पहले सत्र के प्रथम वक्ता डा. मुजम्मिल हुसैन कासमी जामिया मिलिया में मदरसा षिक्षा पर 11 सालों से काम कर रहे हैं। अपने आलेख में उन्होंने देष भर में मदरसों की तस्वीर सामने रखते हुए उनके पाठ्यक्रम में सुधार के अपने अनुभव बताये। उन्होंने कहा, 'मदरसे, भारत में मुस्लिम समुदाय की जिन्दगी हैं।..... आज षिक्षा की मदरसा व्यवस्था पष्चिम, मध्य और दक्षिण एषिया के बड़े हिस्सों में प्रचलित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार असोम में 721 मदरसे 1,20,000 बच्चों को, गुजरात में 1825 मदरसे 1,20,000 से ज्यादा बच्चों को, कर्नाटक में 961 मदरसे 84,864 बच्चों को, केरल में 9975 मदरसे 7,38,000 बच्चों को, मध्य प्रदेष में 6000 से ज्यादा मदरसे 4,00,000 बच्चों को और राजस्थान में लगभग 1780 मदरसे 4,00,000 से ज्यादा बच्चों को षिक्षा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेष में मकतबों की संख्या 15,000 और मदरसों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। इसी तरह बिहार में 3500 मदरसे हैं। भारत के दूसरे राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है। केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी मदरसे केवल मुस्लिम बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। अपनी शुरुआत से ही मदरसे एक पाठ्यक्रम पर चल रहे हैं और इसमें बहुत कम बदलाव आये हैं। हकीकत यह है कि आज लाखों मुस्लिम बच्चे अपनी प्राथमिक और शायद एकमात्र औपचारिक षिक्षा इन मदरसों में पा रहे हैं जहां केवल साहित्य, इस्लामी अध्ययन और सामाजिक विज्ञानों की हल्की–फुल्की जानकारी दी जाती है। रोजगार की बदलती जरूरतों को देखते हुए मदरसों में बच्चों की षिक्षा का स्वरूप बदला जाना चाहिये।.....भले ही मदरसों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ विद्वान पैदा किये हों, पर आज उनके ज्यादातर छात्र बेरोजगार रह जाते हैं।.....केवल मुसलमानों को ही देष की षिक्षा व्यवस्था में कमजोरियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को षिक्षा देने वाले सरकारी स्कूल किसी भी लिहाज से षिक्षा के आदर्ष साधन नहीं कहे जा सकते हैं। इसी तरह मदरसों के बारे में बनी नकारात्मक छवि भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मदरसा षिक्षा में सुधार का विचार नया नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खुद रांची में मदरसा इस्लामिया स्थापित किया था जहां उन्होंने अंग्रेजी की सख्त मुखालिफत के बावजूद अंग्रेजी और गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। मौलाना आजाद ने यह कोषिष 1913 में की थी।'

कासमी साहब ने प्रतिभागियों को बताया कि उन्होंने अपने कामकाज के दौरान 380 मदरसों का सर्वेक्षण किया और दीनी व दुनियाबी तालीम को एकसाथ लाने की कोषिषें जारी रखीं। मदरसा षिक्षकों के 21 दिन के प्रषिक्षण में दीनी तालीम को भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के प्रयास किये

गये। इन कोषिषों के नतीजे 2–3 साल बाद निकले। हमने मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर भी काम किया जिससे षिक्षकों की गिनती बढ़ी और इसने बाकी के लिए एक उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) का काम किया। आज 254 मदरसों में हिन्दी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित काफी हद तक पढ़ाई जाने लगी है। रिहाइषी मदरसों में बच्चों के पूरे समय रहने की वजह से ज्यादा अच्छा काम हुआ। जामिया मिलिया ने मदरसा षिक्षा के बारे में उलमा की कार्यषाला भी आयोजित की जिसमें कुछ ने तो नये पाठ्यक्रम की जरूरत बताई, पर कुछ ने उनको अपने हाल पर छोड़ देने को भी कहा। अपने पर्चे में कासमी साहब ने मदरसों के अपने सर्वेक्षण के विस्तृत आंकड़े भी दिये। उन्होंने यह भी मंजूर किया कि वस्तानिया (मिडिल) स्तर पर मदरसों में दीनी तालीम के बोझ की वजह से गणित, हिन्दी, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन को ठीक से शामिल नहीं किया जा सका है। अपने सर्वेक्षण आंकड़ों से उन्होंने यह भी दिखाया कि दीनी तालीम में यकसानियत के दावों के बावजूद मदरसों में इनका पाठ्यक्रम अलग–अलग है। उन्होंने नतीजा निकाला कि मदरसे साक्षरता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और धीरे–धीरे आधुनिक षिक्षा की तरफ झुक रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको चलाने वाले, मुसलमानों की समाजी और आर्थिक जरूरतें समझ रहे हैं। मदरसों को सेक्युलर और आधुनिक षिक्षा देने तथा मुस्लिम अवाम को जिन्दगी के हर क्षेत्र में भागीदारी दिलाने का माध्यम बनाया जा सकता है। मदरसा आधुनिकीकरण द्वारा पूरे मुस्लिम अवाम का सषक्तीकरण संभव है। उन्होंने मदरसों के सामने आने वाली दिक्कतें भी बताईं। इनमें आधुनिक विषय पढ़ाने वाले योग्य षिक्षकों की कमी, दिल्ली की उर्दू अकादमी द्वारा ठेके पर दिये षिक्षकों का गंभीर न होना, विज्ञान एवं गणित में उर्दू भाषा में षिक्षण–प्रषिक्षण सामग्री का अभाव, कंप्यूटर चलाने के लिए तकनीकी लोगों की कमी तथा मदरसा षिक्षा मूल्यांकन का समुचित तरीका न होना, आदि शामिल हैं।

डा. कासमी ने अपने पर्चे में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदरसा षिक्षा को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया। इसमें अल्पसंख्यकों में षिक्षा पर निगरानी रखने वाली समिति (एनएमसीएमई) द्वारा मदरसा षिक्षा पर विषेषज्ञ समिति गठित करना तथा उसके आधार पर ऐच्छिक मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) से जोड़ना शामिल है। इससे मदरसे अपनी परपरंगत पढ़ाई पर असर डाले बिना आधुनिक विषयों के साथ–साथ व्यावसायिक षिक्षा भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी भी अल्पसंख्यक प्रबंधन वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों/ षिक्षकों के लिए सेमिनार और प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें अब तक 450 प्रधानाचार्य और 950 षिक्षक प्रषिक्षण ले चुके हैं। कासमी साहब ने स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे समाज के कमजोर तबकों तथा नस्ली, समाजी, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों समेत सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण षिक्षा तक पहुंच सुनिष्चित करने के प्रयासों को मजबूत करें। बच्चों को लोकतांत्रिक नागरिक बनाने के लिए षिक्षा तथा लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण आयाम के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिये। उन्होंने विष्वास व्यक्त किया कि एनजीओ अपने प्रयासों से नागरिक भागीदारी बढ़ा कर प्रभावी, ज्ञानवान व प्रतिबद्ध नागरिक तैयार कर सकते हैं। पर्चा प्रस्तुत करने के बाद प्रतिभागियों के सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि दीनी तालीम देने में हम मसलकी मतभेद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सारे मसलकों की दीनी राय बच्चों के सामने रखते हैं और उनको पसंद करने का मौका देते हैं। हमें बच्चों को खोज करने की इजाजत देनी चाहिये। मदरसों में व्यावसायिक षिक्षा के भी कुछ माडल हमारे पास हैं। बच्चों को

हस्तषिल्प के जरिये भी षिक्षा दी जा सकती है जो गांधीजी का नजरिया था। उन्होंने यह भी बताया कि मदरसों के केरल माडल में औपचारिक स्कूली पढ़ाई भी शामिल है। वहां सवेरे मदरसा चलता है और दिन में उसी परिसर में औपचारिक स्कूल, पर हमारे यहां स्कूलों की बदलती षिफ्ट की वजह से यह काम नहीं हो पाता है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति

विक्रमषिला, कोलकाता से आई विषिष्ट अतिथि सुश्री मधुमिता ने पष्चिम बंगाल में मदरसों की स्थिति व अपने संगठन की भूमिका बताते हुए 'प्राथमिक स्तर पर मदरसों में पाठ्यक्रम की एकरूपता' विषय पर अपना पर्चा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मदरसे षिक्षा तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच समाज के सबसे गरीब अल्पसंख्यक तबके तक है। मदरसे उन गरीब बच्चों को षिक्षा के साथ रहने की जगह देकर एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो ऐसा न होने पर शायद जबरिया मजदूरी, जबरन वेष्यावृत्ति या दूसरे किस्म के शोषण का षिकार हो सकते थे। विक्रमषिला, देष के सभी बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण षिक्षा के लिए एक संसाधन केन्द्र के तौर पर काम करती रही है। वह पिछले 10 साल से मदरसा षिक्षा में काम कर रही है क्योंकि पष्चिम बंगाल में मुस्लिम कुल जनसंख्या का 27 प्रतिषत हैं जबकि औपचारिक रोजगार क्षेत्र में उनका हिस्सा केवल 5 प्रतिषत है। वैसे भी 2001 के जनगणना आंकड़े भारत में मुसलमानों के आर्थिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को सामने लाते हैं। इनके अनुसार मुसलमानों में पुरुष साक्षरता 59 प्रतिषत तथा महिला साक्षरता 49 प्रतिषत है। पष्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज में आमतौर पर अपने अलग–थलग पड़ने की भावना घर कर गई है। जैसा कि सच्चर समिति ने भी बताया है कि सर्वषिक्षा अभियान के फायदे मुस्लिम समाज को दूसरों की तरह नहीं मिल पाये हैं। षिक्षा में मुस्लिम बच्चों की भागीदारी प्राथमिक तथा उससे ऊपर के स्तर पर बहुत कम है। मदरसों में भी बच्चे टिक नहीं पाते हैं। यहां तक कि मदरसों में कक्षा 5 से कक्षा 10 तक आते–आते 65 से 70 प्रतिषत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। पष्चिम बंगाल में मदरसा षिक्षा के लिए अलग बोर्ड है और यह देष में अकेला राज्य है जहां अलग मदरसा षिक्षा निदेषालय है। इसके अंतर्गत 560 औपचारिक सेकेन्ड्री स्कूल हैं जिनको हाई मदरसा तथा 400 हायर सेकेन्ड्री स्कूलों को सीनियर मदरसा कहा जाता है। हालांकि इन मदरसों को नियमित समकक्ष स्कूलों के बराबर स्तर दिया गया है, पर असलियत में आगे पढ़ाई या नौकरी के मामले में इनसे निकलने वाले बच्चों के साथ भेदभाव होता है। विक्रमषिला, मदरसा बोर्ड के साथ मिल कर राज्य के दूसरे स्कूलों के बच्चों की तरह इनको गुणवत्तापूर्ण षिक्षा दिलाने

के प्रयास कर रही है। पष्चिम बंगाल सरकार द्वारा मदरसों का समर्थन इस मायने में खास है कि वहां पिछले 20 साल से आधुनिक पाठ्यक्रम चल रहा है और कुछ में तो सह–षिक्षा भी है। कुछ मदरसों में गैर–मुस्लिम बच्चे भी पढ़ने आते हैं और गैर–मुस्लिमों को षिक्षक की नौकरी भी मिली है। सरकार अब अंग्रेजी माध्यम के मदरसे खोलने की योजना बना रही है। यहां निजी मदरसे सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, पर पिछले कुछ महीनों से इनको आर्थिक सहायता तथा मान्यता देने के प्रयास भी हो रहे हैं। सुश्री मधुमिता के अनुसार, पष्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज के सबसे कट्टर तबकों की सोच में भी बदलाव आया है और वे मदरसों में दीनी तालीम के साथ दुनियाबी तालीम के पैरोकार हो गये हैं। मदरसों में रोज दो घंटे का समय आधुनिक षिक्षा के लिए अलग रखा गया है जिसमें राज्य की भाषा बांग्ला, अंग्रेजी और गणित पढ़ाई जाती है। इसे आधुनिक दुनिया में बच्चों के आगे बढ़ने के लिए जरूरी माना जाता है।

पष्चिम बंगाल में मदरसों की अनेक कठिनाइयां भी हैं। यहां आधुनिक षिक्षा के लिए एक या दो षिक्षक ही होते हैं इसलिये वे थोड़े समय में विभिन्न दर्जों के इतने ज्यादा बच्चों को अनेक विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई के लिए विषेष कौषल की आवष्यकता है। विक्रमषिला, षिक्षकों के प्रषिक्षण तथा षिक्षण प्रषिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायता कर रही है। सुश्री मधुमिता ने अपने पर्चे में ऐसी कुछ षिक्षण तकनीकों व षिक्षण सामग्री की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। विक्रमषिला, मदरसों की आवष्यकतानुसार आधुनिक विषयों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता कर रही है। ऐसा करना उच्च षिक्षा के विकल्प खुले रखने के लिए जरूरी है। विक्रमषिला ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम के आधार पर, पढ़ाई के सीमित समय को देखते हुए एक परिवर्तित पाठ्यक्रम तैयार किया है। कक्षा 1 से 4 तक के लिए असरदार षिक्षण प्रषिक्षण सामग्री भी तैयार की गई है। अब तक संस्था ने 500 षिक्षकों को प्रषिक्षित किया है तथा कक्षा 1 से 4 तक छात्रों के लिए अंग्रेजी, बांग्ला व गणित की अभ्यास पुस्तिकायें भी तैयार की हैं। सुश्री मधुमिता ने स्वीकार किया कि निजी (खारिजी) मदरसे कुछ हद तक बहुत ज्यादा औपचारिक षिक्षा लागू करने के बारे में असमंजस की स्थिति में हैं, पर हमें इस सवाल से मुठभेड़ करनी होगी। निजी मदरसों में औपचारिक पाठ्यक्रम शामिल करते हुए हम उनकी खास पहचान और मौजूदगी की वजहों के प्रति बहुत संवेदनषील रहे हैं। उन्होंने मदरसा पाठ्यक्रम में एकरूपता पर बात करते हुए साफ किया कि इसका मतलब मानकीकरण या निजी मदरसों पर पूरे पाठ्यक्रम का भार डालना नहीं समझा जाना चाहिये। इससे बच्चों पर अनावष्यक बोझ पड़ेगा। राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु पर गौर करना तथा सामग्री के चयन पर ध्यान देना जरूरी है। मदरसा पाठ्यक्रमों में एकरूपता, परस्पर संबंध बनाने के लिए जरूरी है, पर ध्यान रखना चाहिये कि मदरसों से बहुत ज्यादा मांग करने की स्थिति में यह उनके और ज्यादा अलग–थलग पड़ने का कारण भी बन सकता है।

बदलाव की जरूरत

पहले सत्र के तीसरे वक्ता, जामिया मिलिया के डा. जसीम अहमद ने अपने पर्चे में मदरसा षिक्षा की क्षमतायें पहचानने, उसमें रचनात्मकता जोड़ने तथा बच्चों को जीवन की नई दिषा देने की बातें विस्तार से रखीं। उनके अनुसार, 'मदरसों को निजीकरण और वैष्वीकरण की मौजूदा दुनिया में बदलाव की जरूरत समझनी चाहिये। नौकरी देने वालों ने खास जरूरतें तय कर रखी हैं और मदरसों का वर्तमान षिक्षा तंत्र ये जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। आज नौकरी चाहने वाले लोगों में बहुत गतिषील व्यक्तित्व जरूरी समझा जाता है, जिनमें कुछ नया बताने और बनाने की योग्यता हो। आने वाले दिनों में आर्थिक दिक्कतों के साथ ही वैष्विक व निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता में कमी होने वाली नहीं है।.....मौजूदा माहौल में जिन्दा रहने और भविष्य की जरूरतों से निबटने के लिए मदरसों को अपने छात्रों तक समकालीन षिक्षा पहुंचाने के तरीके खोजने होंगे। यह समय प्रतियोगिता तथा सबसे बेहतरीन के बचे रहने (डार्विन का सिद्धान्त) का है, इसलिये मदरसों समेत सारे षिक्षण संस्थानों को ऐसे नागरिक तैयार करने की जरूरत है जो प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें और सिद्ध कर सकें कि वे बदलते माहौल में बेहतरीन हैं।'

अपने पर्चे में डा. जसीम ने मौजूदा हालात और मदरसों के कामकाज का विष्लेषण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाये–

1. क्या मदरसा समितियों का भारतीय मुसलमानों की मौजूदा आर्थिक व समाजी जरूरतों के बारे में नजरिया साफ है? क्या मदरसों तथा उसके उत्पादों (छात्रों) के भविष्य के बारे में उनकी समझ साफ है?
2. क्या वे उनकी षिक्षा योजना में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं?
3. क्या मदरसों को सेक्युलर और आधुनिक ज्ञान फैलाने के माध्यम में बदला जा सकता है ताकि नागरिक समाज में मुसलमानों की सहभागिता बढ़ सके?
4. क्या मदरसे के उत्पादों (छात्रों) के जीवन की गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक होता है?
5. क्या मदरसों के आधुनिकीकरण से पूरे समाज का सषक्तीकरण संभव है?'

उन्होंने अपने पर्चे में इन सवालों का जवाब देने की भी कोषिष की और सीखने के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए छात्रों में वैज्ञानिक खोज की भावना पैदा करने पर जोर दिया। यदि मदरसों में विज्ञान और गणित की षिक्षा को बढ़ावा दिया जाये तो यह षिक्षा को ज्यादा सार्थक बना सकता

है। विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने से दिमाग खुलता है तथा बच्चों में तार्किकता, रचनात्मकता व विष्लेषण क्षमता का विकास होता है। यह सारी चीजें आधुनिक व निजीकरण के युग में व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं।

जसीम साहब ने जिक्र किया कि सर सैय्यद अहमद खां ने 1857 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की स्थापना की थी, जिसकी हिन्दुस्तानी मुसलमानों की जिन्दगी और 1857 के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर सैय्यद अहमद खां को मुसलमानों की हालत पर दुख था और वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि मुसलमान पष्चिमी विज्ञानों और दर्षन की दुनिया में होने वाली तमाम तरक्कियों से अपरिचित थे। उन्होंने मुसलमानों से समकालीन षिक्षा पाने और अंग्रेजी जुबान सीखने की अपील की थी। उल्लेखनीय है कि उस समय मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके अंग्रेजी का विरोध करते थे। सर सैय्यद ने मिषनरी भावना से ऐसा मदरसा स्थापित किया जहां मुस्लिम नौजवानों को अपने भविष्य के बारे में निष्चित दिषानिर्देष मिल सके। 'दीन' और 'दुनिया' को संतुलित करने की इस्लामी अवधारणा पर चलते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सारी बाधाओं का मुकाबला किया। उनका लक्ष्य ऐसे संस्थान की स्थापना करना था जहां पूर्वी और पष्चिमी धार्मिक षिक्षा को वैज्ञानिक षिक्षा से जोड़ा जाये। उनके अनुसार, उस समय हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिए न केवल इस्लाम की जानकारी बल्कि तर्कषास्त्र और दर्षन भी जरूरी था। 1864 में मुसलमानों को पष्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की थी। सैय्यद अहमद की लगातार बदलाव की अवधारणा ने मुसलमानों को बहुत फायदा पहुंचाया और मदरसतुल उलूम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विष्वविद्यालय बन गया। यहां से निकले छात्रों ने दुनिया भर में संस्था को अत्यधिक सम्मान दिलाया है। मदरसतुल उलूम का अनुभव आज भी महत्वपूर्ण है, पर बाद में ज्यादातर मदरसे इस लाइन पर नहीं चले। मौजूदा समय में मदरसा चलाने वालों में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है ताकि वे केवल इस्लामी विद्वान ही न पैदा करें बल्कि सभी क्षेत्रों में काम करने वाले आधुनिक विद्वान भी तैयार करें। ऐसा करने से ही मुसलमानों की छिपी क्षमतायें सामने आयेंगी और वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर जगह पाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकेंगे।

डा. जसीम अहमद ने मदरसा षिक्षा का एक माडल पाठ्यक्रम की अवधारणा भी पेष किया जिसमें इस्लामी षिक्षा–35 प्रतिषत, गणित व विज्ञान– 25 प्रतिषत, सामाजिक विज्ञान–20 प्रतिषत तथा भाषा को 20 प्रतिषत स्थान मिलना चाहिये। उन्होंने कार्य आधारित सीखने पर जोर दिया जिसके लिए बेहतर षिक्षक–छात्र संबंध सबसे जरूरी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए खेल गतिविधि, शैक्षिक खेल, शैक्षणिक यात्रा, नाटक करने, खोजने व समस्या हल करने के दृष्टिकोण, खुले तथा बच्चों की रचनात्मकता सामने लाने वाले व प्रतियोगितात्मक माहौल देने की पुरजोर पैरवी की।

प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई की सुश्री रत्ना माथुर ने अपने संक्षिप्त संबोधन में आषा प्रकट की कि षिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद प्राथमिक षिक्षा की स्थिति में सुधार आयेगा। उन्होंने विद्वान वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत आलेखों को बहुत महत्वपूर्ण बताया तथा नालन्दा को मदरसों के बीच बेहतर सोच बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से मदरसों में बेहतर पढ़ाई हो रही है और अब मदरसों को लड़कियों की षिक्षा के

मामले में भी बड़े पैमाने पर सामने आना चाहिये। लड़कियों की षिक्षा के खास सवाल भी सामने आने चाहिये। षिक्षा की गुणवत्ता लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के प्रयास होने चाहिये। सुश्री माथुर ने माना कि सरकारी षिक्षा के ढांचे में बहुत सी चीजें शामिल नहीं हैं जिनको पूरा करने में षिक्षाषास्त्री और षिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुश्री रत्ना माथुर ने अपनी संस्था की ओर से ऐसे प्रयासों के लिए भविष्य में भी सहायता का आष्वासन दिया। गौरतलब है कि इस सेमिनार का वित्तपोषण सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने किया था।

प्रतिभागियों से संवाद

प्रथम सत्र के अन्त में प्रतिभागियों ने अनेक सवाल पूछे जिनका वक्ताओं ने जवाब दिया। लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता शकील सिद्धीकी ने पूछा कि एनसीईआरटी मदरसा षिक्षा के लिए क्या कर रही है? मदरसा षिक्षा में अलग–अलग मसलकों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाये? तथा मदरसा पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कितनी जगह बचेगी? डा. मुजम्मिल हुसैन कासमी ने इसके जवाब में बताया कि एनसीईआरटी मदरसा षिक्षा पर लगातार सेमिनार कर रही है और हाल ही में उसने दसवां सेमिनार किया है। वह सभी मदरसों की स्थिति का अध्ययन कर उनमें साझा लाभदायक चीजों की तलाष कर रही है। जहां तक इस्लाम के अलग–अलग मसलकों के बीच मतभेदों का मामला है तो बेहतर है कि शुरुआती स्तर पर सभी मसलकों की चीजें बता देनी चाहिये। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल है तो एनसीईआरटी चाहती है कि पांचवे दर्जे तक की षिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिये। मदरसा षिक्षा से लंबे समय से जुड़े रहे।

मदरसा दारूल उलूम बाराबंकी के प्रधानाचार्य अब्दुल रज्जाक नदवी ने अपनी राय सामने रखते हुए कहा कि मदरसा प्रबंधकों की सोच बदलना बहुत जरूरी है। अगर वे चाहें तो पाठ्यक्रम में एकरूपता हो सकती है। इस समय उत्तर प्रदेष में कई पाठ्यक्रम चल रहे हैं। क्या इस बारे में मदरसा प्रबंधकों की बैठक बुलाई जा सकती है? उन्होंने नालंदा का षुक्रिया अदा करते हुए खुषी जाहिर की कि दुनियाबी तालीम के बारे में मदरसों में समझ बेहतर हो रही है जिसमें नालन्दा जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। डा. जसीम अहमद ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि मदरसों से बहुत से सफल लोग निकले हैं, पर इसकी वजह यह है कि मदरसों से निकलने के बाद वे दुनियाबी हुनरों की ओर गये। उन्होंने ऐसे सफल लोगों के कई उदाहरण भी दिये। मसलकों के बीच मतभेदों के बारे में उनका कहना था कि मसलकों के बारे में बाद में बताया जा सकता है, पर शुरुआती सतह पर इस्लाम की मूलभूत जानकारियां दी जानी चाहिये जिनके बारे में कोई

मसलकी मतभेद नहीं हैं। प्रयत्न फाउंडेषन की नाहीद ने कहा कि मदरसों में आने वाले बच्चों के मां–बाप बहुत गरीब होते हैं और मदरसों के काम काज के बारे में कोई प्रचार भी नहीं होता है। मदरसे में आने वाले बच्चों के मां–बाप से संबंध बनाये रखने चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार और अमीर लोगों की तरफ से मदरसों को पैसा मिलता है, पर वे उसका ठीक से फायदा नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि लड़कियों के लिए कितने मदरसे हैं? उनकी तालीम के बारे में क्या सोचना है? अपने जवाब में सुश्री रत्ना माथुर ने समाज में व्याप्त पुरुषवादी नजरिये पर प्रकाष डाला जिसका असर हर तबके पर पड़ता है। यही वजह है कि जहां गरीब से गरीब आदमी पैसा खर्च करके लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है वहीं लड़कियों को मदरसे में भेजता है। उन्होंने यह भी बताया कि लड़कियों के लिए मदरसे बहुत कम हैं पर अब उनकी गिनती बढ़ रही है। बेटी फाउंडेषन के खजान सिंह ने कहा कि षिक्षा को केवल मानव पूंजी या उद्योगों के उत्पादों की तरह नहीं देखा जाना चाहिये। यह नजरिया ठीक नहीं है। बच्चों में वैज्ञानिक मिजाज का विकास करने की कोषिषें होनी चाहिये और इस दिषा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने काफी काम किया है। डा. जसीम अहमद ने अपने जवाब में कहा कि आज दुनिया भर में भौतिकवादी दृष्टिकोण फैल गया है और षिक्षा को ज्यादातर उत्पाद के विचार से ही देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि औसतन सभी बच्चों का जेहन एक समान होता है। विज्ञान की षिक्षा को सामाजिक षिक्षा से भी जोड़ा जा सकता है जैसे हवा में अलग–अलग गैसें होती हैं और उनका सही मिश्रण ही सबके लिये लाभदायक होता है। भले ही आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है पर आक्सीजन की थोड़ी कमी या कार्बन डाई आक्साइड की थोड़ी बढ़ोत्तरी हमारी जिन्दगी को मुसीबत में डाल देती है, यही हालत समाज में रहने वाले अलग–अलग तबकों की है जिनके बीच आपसी दोस्ती और शांति जरूरी है।

नालन्दा के आसिम सिद्दीकी ने विक्रमषिला की सुश्री मधुमिता से पूछा कि पष्चिम बंगाल के सरकारी मदरसों में दीनी तालीम का क्या नज्म है? वहां अरबी को केवल भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है? क्या इन्हें मदरसा कहा जा सकता है? दूसरा प्रष्न यह है कि जो छोटे मदरसे अपने खुद के संसाधन से चल रहे हैं उनके लिए विक्रमषिला क्या कर रही है? सुश्री मधुमिता ने बताया कि सरकारी मदरसों में केवल सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जिसमें दीनी तालीम शामिल नहीं है। सरकार निजी मदरसों की कोई मदद नहीं कर रही है। हमारी संस्था षिक्षक प्रषिक्षण तथा छोटे मदरसों की हालत सुधारने पर जोर दे रही है। सरकारी मदरसों में सहषिक्षा है। अफ्सोस की बात है कि प्राइवेट मदरसों में लड़कियां बिल्कुल नहीं जाती हैं और समाज के सबसे गरीब तबके में लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजा जाता है।

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के प्रो. एस. एस. ए. जाफरी लंबे समय से प्रदेष में मुस्लिम समाज की आर्थिक व समाजी स्थितियों के अध्ययन और मदरसा षिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगे रहे हैं। उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों से वादा किया कि वे जल्द ही मदरसा षिक्षा के प्रभाव पर एक अध्ययन करके सबके सामने लायेंगे। उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण की सफलता के लिए मदरसा प्रबंधकों को अपने आंदोलन में शामिल करने की

जरूरत बताई। आजादी तक मदरसों ने देष को बहुत से महत्वपूर्ण लोग दिये हैं। मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए जाफरी साहब ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) में मदरसों के बच्चों को शामिल करने के फायदे बताये। उन्होंने एनआईओएस में भर्ती होने की प्रक्रिया भी बताई। उन्होंने समाज के पढ़े लिखे लोगों को मदरसों में जोड़ने की जरूरत भी बताई और कहा कि रिटायर्ड लोग मदरसों में पढ़ा सकते हैं, बस इसके लिए मदरसा प्रबंधकों को थोड़ी कोषिष करनी होगी। डा. मुज्जमिल हुसैन कासमी ने एनआईओएस के फायदों और पाठ्यक्रम के बारे में जाफरी साहब की बातों से सहमति प्रकट की। सुश्री रत्ना माथुर ने षिक्षा के उत्पादों के मामले पर कहा कि बाजार के लिए हमें अपनी संस्कृति और बेहतरीन मानव मूल्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर बाजार के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए हमें बीच का एक रास्ता निकालना होगा।

आधुनिक युग की जरूरतें

दूसरे सत्र के पहले वक्ता दिल्ली विष्वविद्यालय के डा. नईमुल हसन ने आधुनिक युग में मदरसा पाठ्यक्रमों पर अपना पर्चा पेष किया। उन्होंने बताया, 'भारत में मदरसे दो प्रकार के हैं।

बिहार, बंगाल, झारखंड, असोम, उत्तर प्रदेष और केरल में कुछ मदरसे राज्य सरकारों से जुड़े हैं। छोटे होने के बावजूद इनको राज्य सरकार से तनख्वाहें तथा दूसरी सहायता मिलती है। ये इस्लामी अध्ययन के साथ राज्य सरकार द्वारा स्कूलों या कालेजों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। समुदाय आधारित मदरसे चार प्रकार के हैं—मकतब, दारुल कुरान, मदरसा और जामिया। इनका स्तर क्रमषः स्कूल, हाई स्कूल, कालेज और विष्वविद्यालय के बराबर है। हालांकि आम आदमी इन सबको मदरसा कह देता है, पर यहां हमारी चर्चा दूसरे प्रकार के 'मदरसों' के बारे में है जो मुसलमानों के पैसे से और उनके द्वारा चलाये जाते हैं..... अनेक प्रसिद्ध इस्लामी संस्थानों और मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है तथा भारत के

ज्यादातर गैर–सरकारी मदरसे इनसे किसी न किसी तरह जुड़े हैं। इन संस्थानों में दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलेमा लखनऊ, जयपुर का जमीयतुल हदीया, बनारस का जामिया सलफिया और मुबारकपुर का जामिया अषरफिया शामिल हैं। इन सभी मदरसों और जमीयत का समग्र पाठ्यक्रम दर्से निजामी पर आधारित है। दारुल उलूम देवबंद का मौजूदा पाठ्यक्रम चार स्तरों का है और इसमें छात्रों को उर्दू, फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, अरबी व्याकरण एवं वाक्य रचना पढ़ाई जाती है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए लखनऊ के नदवतुल उलेमा ने अपने पाठ्यक्रम में दूरगामी परिवर्तन किये हैं। इसमें उत्तर प्रदेष बोर्ड के समान ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।.....जमीयतुल हिदिया, जयपुर के पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान तथा गहन तकनीकी प्रषिक्षण शामिल है। जामिया स्तर पर आधुनिक विज्ञान बाकी कालेजों के स्नातक स्तर की तरह हैं तथा तकनीकी षिक्षा भी सार्टिफिकेट कोर्स के समान है। इसी तरह जामिया सलफिया, बनारस के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कुछ तकनीकी प्रषिक्षण शामिल है।'

मदरसा षिक्षा की समस्यायें बताते हुए डा. नईमुल हसन ने सभी मदरसों को नियंत्रित करने वाली केन्द्रीय एजेंसी न होने, बड़े मदरसों में आधुनिक षिक्षण विधियों का प्रयोग न होने तथा यहां के छात्रों में आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता न होने को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सार्थक शोध और खोज मदरसों के लिए पुराने जमाने की बात हो गई है। मौजूदा उलेमाओं को पुराने स्वर्णिम काल से सबक लेना चाहिये नहीं तो बहुत देर हो जायेगी। आधुनिक ज्ञान न होने के कारण मदरसों के स्नातक न अपनी आर्थिक हालत बेहतर कर पाते हैं और न मुस्लिम समाज को रास्ता ही दिखा पाते हैं। मदरसों की ज्यादातर डिग्रियों को अलीगढ़ मुस्लिम विष्वविद्यालय और जामिया मिलिया के धर्मषास्त्र विभागों के अलावा कहीं मान्यता नहीं मिलती है। इन डिग्रियों के बाजार में बेकार होने की वजह से उनका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं होता है। मुस्लिम विचारकों का एक तबका वर्तमान जरूरतों को देखते हुए मदरसा षिक्षा के आधुनिकीकरण के पक्ष में है, पर वे मुष्किल से ही उन कट्टर इस्लामवादियों की खिलाफत करते हैं जो इस्लामी मदरसों को आधुनिक बनाने के बजाय आधुनिक षिक्षण संस्थानों को मुस्लिम बनाने की पैरवी करते हैं। मदरसों के षिक्षकों का वेतन बहुत कम और लगभग नगण्य है। इसके कारण मदरसों में अच्छी गुणवत्ता वाली षिक्षा बहुत मुष्किल है। वास्तव में मदरसे आने वाले छात्र बहुत गरीब तबके के होते हैं और ज्यादातर मदरसों द्वारा मुफ्त आवास सुविधा के कारण यहां पढ़ना ऐसे छात्रों के लिए सुविधाजनक होता है।

मदरसा षिक्षा की समस्यायें हल करने के लिए डा. नईमुल हसन ने अनेक सुझाव भी दिये जिनमें मदरसों द्वारा मौजूदा बदलावों के बारे में छात्रों को बताना, पाठ्यक्रम में समय के अनुसार बदलाव, विभिन्न मदरसों के बीच सहयोग, सीबीएसई की तरह एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की जरूरत, मदरसों में आधुनिक व एलेक्ट्रानिक उपकरणों की जरूरत तथा मदरसा प्रबंधकों के बीच एक समन्वय समिति बनाने की बाते प्रमुख थीं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भविष्य में केन्द्रीय मदरसा बोर्ड बनाने की घोषणा अच्छा कदम है। इससे भारत में मदरसों की षिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से मदरसों में अच्छा पाठ्यक्रम होने के बावजूद उसके सही अमल में गड़बड़ी होती है। बहुत सी जगहों पर सरकारी पैसा आने के बाद जैसे मदरसा प्रबंधकों की

जवाबदेही ही खत्म हो गई है, अब जवाबदेही न खुदा के लिए है न सरकार के लिए। बहुत से लोग इसी डर से सरकारी आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहते हैं कि आडिट शुरू हो जायेगा। मसलकों के मामले में उनका कहना था कि जिस तरह राज्य का कोई मजहब नहीं होना चाहिये उसी तरह मदरसों का कोई मसलक नहीं होना चाहिये। सभी मदरसों के पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करने के बाद उनमें यकसानियत लाने के लिए यह सोच जरूरी है। इसके लिये मदरसा चलाने वालों के साथ बैठकें और कार्यषालायें करने की जरूरत है।

पाठ्यक्रम में एकरूपता

दूसरे सत्र के दूसरे वक्ता श्री शकील सिद्दीकी उर्दू व हिन्दी के कहानीकार, लेखक तथा दोनों भाषाओं में परस्पर अनुवाद के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया है जिसे राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने छापा है। अपने पर्चे में उन्होंने मुष्किलों के बावजूद पाठ्यक्रम की यकसानियत की जरूरत पर जोर देते हुए ऐसा करने के तरीकों पर सुझाव भी दिये। उन्होंने कहा, 'मदरसों के पाठ्यक्रम में यकसानियत इसलिये भी जरूरी है कि इसमें तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए यह व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हो सके। हमें याद रखना चाहिये कि 18वीं शताब्दी में दर्से निजामी की शुरुआत मदरसा तालीम में यकसानियत लाने और उसे ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए ही की गई थी। किन्हीं मजबूरियों या परेषानियों के कारण एक मदरसे से दूसरे मदरसे में जाने की हालत में पाठ्यक्रम में एकरूपता के फायदे ज्यादा साफ हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेष में ही एक साथ कई तालीमी बोर्ड काम कर रहे हैं....एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाने पर होने वाली दिक्कतों का तजुर्बा बहुत से लोगों को होता है। केन्द्रीय बोर्डों से सूबाई बोर्डों में आने वाले बच्चों को माध्यम बदलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।....मदरसा तालीम में यकसानियत की कमी पर नजर डालने से पता चलता है कि मुल्क और सूबे की तो बात छोड़िये एक–एक जिले के अलग–अलग मदरसों में अलग–अलग पाठ्यक्रम चलता है। कहीं दारुल उलूम का तो कहीं नदवतुल उलेमा का, कहीं मरकजी मक्तवाये इस्लामी का तो कहीं मजहारूल उलूम का। उत्तर प्रदेष दीनी तालीमी कौंसिल का भी एक पाठ्यक्रम है और काफी मदरसे इससे जुड़े हैं। इसी तरह सूबाई अरबी फारसी बोर्ड का अलग पाठ्यक्रम है। मजेदार बात है कि कहीं–कहीं मुदर्रिस खुद ही अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम तय कर लेते हैं।' उन्होंने अलग–अलग पाठ्यक्रमों में इस्लाम के अलग–अलग मसलकों के हिसाब से भिन्नताओं का भी जिक्र किया। हालांकि, मतभेदों का मामला इतना संगीन नहीं है पर यकसानियत की बात करते हुए हमें इसे ध्यान में रखना होगा। हर मसलक को अपनी बात कहने

का हक है क्योंकि हमारे देष के संविधान ने हर शहरी को हक दिया है कि वह अपने मजहबी रसूमात अपने अकीदे के हिसाब से अदा करने और इस तरह से षिक्षा देने के लिए आजाद है।

शकील साहब ने खुषी जाहिर की कि अब मदरसों में सहषिक्षा का रिवाज बढ़ रहा है और ज्यादातर प्राइमरी स्तर पर लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कट्टरपंथियों का विरोध भी पहले जैसा कड़ा नहीं रह गया है। पाठ्यक्रम में एकरूपता पर बात करते समय हमें इस बात पर भी जरूर गौर करना चाहिये कि इनमें लड़कियों के लिए जरूरी कुछ खास हुनर जरूर शामिल किये जायें। उन्होंने साफ कहा कि 'यों तो मेरे ख्याल से लड़के–लड़कियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। फिर भी लड़कियों की तालीम को खास अहमियत देने या उनको मदरसों की ओर आकर्षित करने के लिए अगर कुछ खास चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी महसूस हो तो उस पर गहराई से गौर करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिये। प्राइमरी स्तर पर पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए उसका ढांचा ऐसा बनाया जाये कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र अपनी पढ़ाई के बाद अगर दूसरे बोर्डों या गैर–मजहबी तालीम में जाना चाहें तो उनको दिक्कत न हो।' मदरसा षिक्षा में दीनी तालीमी कौंसिल की कोषिषों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में जरूरी बदलावों की समझदारी पैदा की, अपने मदरसे भी खोले और आधुनिक पाठ्यक्रम भी लागू किये। इसलिये पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के प्रयासों में हमें इस कौंसिल का सहयोग हासिल करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

गुजरात के मदरसे

इस सत्र के अन्तिम वक्ता गुजरात से पधारे डा.हाजीभाई बादी, लोकभारती संस्था से जुड़े हैं। डा.बादी पी0टी0सी0 कालेज, भावनगर में प्रोफेसर हैं और मदरसा षिक्षा तथा षिक्षक प्रषिक्षण में उनका लंबा अनुभव है।

पूरे देष में षिक्षा की स्थिति पर सरसरी नजर डालते हुए उन्होंने कहा, 'भारत की 11 पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च षिक्षा को ही केन्द्र में रखा गया था। इसके लिए बजट को बढ़ा कर 7.7 प्रतिषत से बढ़ाकर 15 प्रतिषत कर दिया गया है। इसकी वजह से आईआईटी और आईआईएम से टेक्नोक्रेट और प्रषासक पैदा हो रहे हैं। भारत विष्व में आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत में हर साल 25 लाख स्नातक पैदा होते हैं, जो सारे भारतीय युवा वर्ग के केवल 10 प्रतिषत हैं। इसका मतलब है कि 90 प्रतिषत की षिक्षा का कोई ठिकाना देष में नहीं है। सोचने से पता चलता है कि इसके मूल में प्राथमिक षिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था है।.....भारतीय संसद ने 2002 में 82वें संषोधन द्वारा प्राथमिक षिक्षा को मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया है, पर हालत क्या है? भारत की कुल आबादी में 40 प्रतिषत निरक्षर हैं यानि कि 1.7 अरब में 42.80 करोड़ लोग निरक्षर हैं।

इनमें महिलाओं में 54 प्रतिषत और पुरुषों में 75 प्रतिषत लोग साक्षर हैं। बाकी के बारे में हम क्या सोचते हैं?....देष में 11,24,033 पाठषालायें काम कर रही हैं। इनमें 1,22,355 पाठषालाओं में एक षिक्षक है जबकि 21,899 पाठषालाओं में एक भी षिक्षक नहीं है। 32,000 पाठषालाओं में एक भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता है। देष की 90,000 पाठषालाओं में ब्लैकबोर्ड तक नहीं है। आज भी देष के 19 करोड़ 4 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यह भारत के आम समुदाय की बात है। मुस्लिम समुदाय की तो बात ही क्या करें?'

गुजरात की स्थिति के बारे में डा. हाजीभाई ने बताया कि वहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। मदरसे भी बहुत कम और मस्जिदों से जुड़े हैं। बच्चे सवेरे मदरसे जाते हैं और बाद में स्कूल। वहां कोई मदरसा बोर्ड नहीं है। मदरसों में दीनी तालीम हर मसलक की अलग–अलग है, पर दुनियाबी तालीम सभी जगह गुजरात बोर्ड की है। कुछ मदरसे केवल दीनी तालीम ही देते हैं। मुस्लिम समाज षिक्षा के मामले में हाषिये पर है। उन्होंने कहा, 'गुजरात में एनसीईआरटी की स्थापना 1988 में हुई थी।... गुजरात के मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलता है। इसके लिये कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि गुजरात में मदरसों की संख्या बहुत कम है। ..... अल्लाह के महान पैगम्बर मोहम्मद साहब ने फर्माया है कि –हर मुस्लिम मर्द और औरत को इल्म सीखना फर्ज अैन है और आगे फरमाया कि–इल्म सीखने हेतु चीन तक भी जाना चाहिये। इतने महत्वपूर्ण आदेष के बावजूद भी हम सोते हैं, कब तक सोयेंगे?' षिक्षक प्रषिक्षण के अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि षिक्षा कार्य आधारित, आनन्ददायी, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, जीवनोपयोगी, गुणवत्तापूर्ण तथा शारीरिक षिक्षा व संगीत को समाहित करने वाली होनी चाहिये। उन्होंने छात्रों के माता–पिता के साथ बैठकें करने और षिक्षक प्रषिक्षण के नवीनीकरण पर जोर दिया। डा. हाजीभाई ने साफ कहा कि मुस्लिम समाज को भारतवर्ष का सषक्त नागरिक बनना चाहिये जिसके लिये हमें मुख्यधारा के अनुकूल बनना जरूरी है।

समस्यायें और सुझाव

दूसरे सत्र के बाद खुला सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी समस्यायें बताई जिनके जवाब वक्ताओं तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डा. मुजम्मिल हुसैन कासमी ने दिये। प्रतिभागियों ने सेमिनार के बाद काम करने के बारे में अनेक सुझाव भी दिये। षिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़े रहे, बाराबंकी निबलेट कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य मुहम्मद जियाउल खान वारसी ने जानना चाहा कि मातृभाषा किसे माना जाये? इस सवाल पर काफी प्रतिभागियों ने अपना नजरिया सामने रखा।

एक प्रतिभागी का कहना था कि त्रिभाषा फार्मूले के हिसाब से बच्चा मां से जो भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा समझी जानी चाहिये। इस पर सवाल उठा कि यदि द्विभाषी परिवार यानी मां और बाप की अलग–अलग भाषा हो तो बच्चे की मातृभाषा क्या मानी जायेगी? यह दिक्कत भी सामने आई कि अगर उर्दू षिक्षक नहीं है और बच्चा स्कूल व आसपास के माहौल से हिन्दी या कोई दूसरी भाषा बोलना सीखता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? आखिरकार खुद वारसी साहब ने ही नतीजा निकाला कि कोई आदमी जिस जुबान में सोचता है और वह उसके माने नहीं पूछता वही उसकी मातृभाषा होनी चाहिये। गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के प्रो. एस. एस. ए. जाफरी ने उत्तर प्रदेष में अपने संस्थान द्वारा कराये मुस्लिम समाज के सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि लगभग 4–5 प्रतिषत बच्चे मदरसे जाते हैं जबकि 35 प्रतिषत बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं बल्कि काम करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़कियों के मदरसों में महिला षिक्षक होनी चाहिये। उन्होंने सवाल किया कि पहले खाते–पीते मुस्लिम परिवारों के घरों में लड़कियों के मदरसे चलते थे, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सत्र की अध्यक्षता कर रहे मुजम्मिल साहब ने कहा कि मदरसों को एनआईओएस से जोड़ना चाहिये तब षिक्षकों को वेतन मिलेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार के एक आदेष का भी जिक्र किया जिसके अनुसार पंजीकृत मदरसों में स्नातक षिक्षक के लिए 6000 और प्रषिक्षित षिक्षक के लिए 12000 रुपये वेतन मिल सकता है। केन्द्रीय मदरसा बोर्ड बनाने के मामले पर हालिया मतभेद और विरोध के बारे में एक प्रतिभागी के सवाल पर उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों में शक है कि अगर सरकार पैसा देगी तो दीनी तालीम से छेड़छाड़ करेगी। भले ही इस शक की बुनियाद मजबूत न हो पर एक सच्चाई यह है कि सरकारी पैसा मिलने के बाद मदरसे का कामकाज ठप हो जाता है। इसके बारे में भी गहराई से सोचने की जरूरत है। अब्दुल रज्जाक नदवी ने सुझाव दिया कि नालन्दा और ऐसी संस्थाओं के लोग सारे मदरसा पाठ्यक्रमों का गहराई से अध्ययन कर एक पाठ्यक्रम तैयार करें। उन्होंने नालन्दा से हर जिले में अपना एक माडल मदरसा खोलने का भी अनुरोध किया ताकि दूसरे लोग इसके नक्षेकदम पर चल सकें। एक प्रतिभागी ने कहा कि हमें जामिया के अनुभव से सबक लेना चाहिये। एक अन्य प्रतिभागी का मानना था कि दुनियाबी षिक्षा के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपना लेना बेहतर होगा तथा लड़कियों की षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

सेमिनार के अन्त में नालन्दा मदरसा षिक्षा कार्यक्रम के संयोजक आसिम सिद्दीकी ने विषिष्ट अतिथियों, सभी प्रतिभागियों तथा सहभागी षिक्षण केन्द्र को धन्यवाद देते हुए मदरसा षिक्षा में पाठ्यक्रम की एकरूपता लाने व उसे बेहतर बनाने के लिए नालन्दा की ओर से लगातार प्रयासरत रहने का वादा किया।

सेमिनार के मुख्य सुझाव

- मदरसों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रम/पुस्तकों का अध्ययन होना चाहिए। जिससे पाठ्यक्रम में निहित दक्षताओं को समझा जा सके।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उनके माडल प्रारूप तैयार किए जाएं इन माडल प्रारूपों के आधार पर एक विजन विकसित किया जाए और इस विजन को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स पर्सन तैयार किए जाएं और ये रिसोर्स पर्सन प्रषिक्षण दें।

- नया पाठ्यक्रम प्रारूप बनाने के लिए अलग–अलग मसलक के जानकार व षिक्षाविद की मदद ली जाए।
- मदरसों में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में एन0सी0ई0आर0टी0 एवं राज्य सरकार के बेसिक षिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निहित दक्षताओं का भी समावेष किया जाए।
- प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम विषेषकर असरी तालीम को मसलक से अछूता रखा जाए बल्कि बच्चों की विषयगत दक्षताओं को केन्द्र बिन्दु में रखना चाहिए।
- एक समान प्राथमिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए मदरसों को जागरूक बनाने की जरूरत है इसके लिए ब्लाक अथवा जिला स्तर पर बातचीत षुरू करने की जरूरत है।
- पाठ्यक्रम में लड़कियों के लिए उनकी जरूरियात के मुताबिक दक्षताओं का समावेष हो।

Papers Presented in Seminar

Revamping Madrasa Curriculum at Elementary Level of Education : An Experiment with Selected Madrasas of Delhi.

(Muzammil Husain Quasmi, Asstt. Professor, Deptt. Of TT&NFE (IASE), Jamia Millia Islamia, New Delhi)

Introduction

Madrasas are the lifelines of Muslim community in India. "Madrasa is an institution of learning, where Islamic sciences including literary and philosophical ones are taught" (Encyclopaedia of Islam - Leiden E.J.Brill). Avowed aim of madrasa education is to inculcate the belief and practice of Islam among its followers and guide them to follow Kuran and traditions of the Prophet. The foundation of Madrasa education is therefore, basically standing on two pillars of Quran (Collection of God's revelations to Prophet Mohammad) and Sunna (Tradition of Prophet Mohammad). Madrasas are working under the Constitution's Article 29 (1) and Article 30 (1). Any tampering with their system and syllabus is wrong. The Constitution has given the minorities the right to open and run institutions of their choice.

Today, the *Madrasa* system of education is prevalent in large parts of West, Central, and South Asia. The number of *Madrasas* in India is estimated to be between thirty to forty thousand. According to the Ministry of Home Affairs, Government of India, there are 721 *Madrasas* catering to over 1,20,000 children in Assam, 1,825 *Madrasas* catering to over 1,20,000 children in Gujarat, 961 for 84,864 children in Karnataka, 9,975 for 7,38,000 children in Kerala, 6,000 for over 4,00,000 children to Madhya Pradesh and some 1,780 catering to over 25,000 children in Rajasthan. In Uttar Pradesh, the number of *maktabs* is more than 15,000 and *Madrasas* over 10,000 and there are 3,500 *Madrasas* is Bihar. Similar are the figures for the other States of India. Except in some parts of Kerala, these *Madrasas* cater strictly to Muslim children. Ever since their emergence, the *Madrasas* have persisted with a curriculum that has seen few changes. The fact that literally lakhs of Muslim children acquire their primary, and perhaps their only formal education, in these *Madrasas* where only literature and Islamic studies with a cursory knowledge of social sciences. The format of the education imparted to the students of Madrasas ought to be modified keeping in view the shifting demands of the employers – a concern which can no longer be under-played. And this is perfectly possible without an erosion of the cultural and religious identity. The role being played by Madrasa education system in India was reflected in the enthusiastic participation during the two-day national seminar (March 29-30, 2008) held at the Jawaharlal Nehru University (JNU). While it was accepted that the madrasa education system has produced some scholars of international fame, it was also pointed out that majority of *talaba* remains deprived of job opportunities. At the same time, attention was also paid to the fact that only Madrasas should not be held responsible for the weaknesses the country's education system is suffering from. The government schools reaching out to poor people in rural areas can from no angle be held to be centers of ideal means of education. It was also pointed out that a negative image held about Madrasas was not absolutely correct.

Revamping of Madrsa Curriculum is not a new idea. Maulana Azad himself established a Madrasa Islamia in Ranchi where he introduced English and Mathematics inspite of severe opposition to English.

Need of the Study

In this context it becomes necessary to stress that science education, coupled with modern technology, if put to proper use in *madrasas*, could probably make education more meaningful. In modern times, there has been a paradigm shift in the business of education from 'teaching' to 'learning'. Madrasas are no longer exception to this. It is a demonstrated fact that much learning can happen if the student is left to himself in the proper environment, with the proper resources, tools, and most of all, with proper guidance. Fundamental changes in the educational system may be possible, and indeed essential.

Keeping these views in mind, the Department of Teacher Training and Non Formal Education took a pioneer project to study the Madrasas of Delhi. An intensive survey of 380 Madrasas and Maktabs carried out under the leadership of Prof. M. Akhtar Siddiqui the present Chairman of NCTE. Simultaneously, 21 days in-service teacher training programme started for Madrasa teachers to orient them towards modern methods of teaching. Few selected topics from science, social science, English and Math were also introduced to arouse their interest in these subjects. Besides, computer training were also imparted to them. These teachers served as a catalyst adopt modern subjects, technology and methods of teaching in their respective institutions. As a result a very positive change took place intertwined with government Madrasa Modernization Scheme. The scheme of Financial Assistance for Modernisation of Madrasa Education has formulated with a view to providing financial assistance for introducing science, mathematics, social studies, Hindi and English in the curriculum of madarasas and Muktabs. It wassaid that this scheme will help to initiate the process of Modernisation of these traditional institutions and cent per cent assistance will be given by the Ministry to such institutions for appointment of qualified teachers for teaching the new subjects to be introduced. The scheme is being implemented through the State Governments.

Survey Results
Enrolment N=254

Age Group	Boys	Girls	Total
6 – 11 years	13,766	9,688	23,454
11 – 14 years	8,880	3,784	12,664
Total	**22,646**	**13,472**	**36,118**

Modern subjects introduced at Ibtadai (Primary) Level

Subjects	No. of Madrsas
Mathematics	40
English	36
Hindi	41
Environmental studies	40

Modern subjects introduced at Wastania (Middle) Level

Subjects	No. of Madrsas
Mathematics	13
English	09

Hindi	11
Environmental studies	12

Need for uniform Curriculum

Despite the claim for uniformity in religious content of curriculum different Madrasas have adopted different courses and content of curriculum at different level of teachings. The following tables reveal courses and content in different classes of Ibtadai (primary) level of education.

1. **Aedadia Level (Preparatory)** **N=199**

Courses/Subjects	No. of Madrasas
Qaida Baghdadi	199
Noorani Qaida	185
Yassaranal-Quran	192
Urdu Qaida	143
Ginti 1 – 100 (numerals)	190

2. **Aedadia Awwal (class I)** **N=199**

Courses/Subjects	No. of Madrasas
Urdu ki pahli kitab	165
Hindi Prataham/ Manohar pothi	45
Pana jana	189
English (preparatory level)	28
Math (Pahara)	60
Amma Para (Recitation)	198
Quran (Nazra)	175
Kalima recitation	192
Games	39

3. **Aedadia Thani (class II)**

Courses/Subjects	No. of Madrasas
Quran	199
Qirat	161
Games	30
Kalima	171
Math	34
English	63
Hindi	49
Diniat	136
Mashaqui	103
Dictation	104
Value Education	71
Village Panchayat	27
Libas ka Taaruf (EVS)	173

4. **Aedadia Thalis (class III)**

Courses/Subjects	No. of Madrasas
Pharsi ki Pahli	31
Qirat/Tajweed	152
Arabi / Adab Exercise	10
Dini Taleem	168
Mashaqui	109
Dictation	73
Hindi	80
English	64
Mathematics	80
Games	32
Method of Salat	183
Hamari dunia	68

5. **Aedadia Raabe (class IV)**

Courses/Subjects	No. of madrasas
Pharsi ki Dosri Kitab	31
Qirat	135
Tajweed	32
Arabi	31
Arabi Exercise	28
Diniat	145
Math	56
Hindi	73
Urdu	152
English	78
Hamari Badshahi	62
GAMES	25
Method of Salat	192

6. **Aedadia Khamis or Arabi Awwal (class V)**

Courses/Subjects	No. of madrasas
Pharsi (Gulistan)	28
Grammar (Amadnama)	03
Qirat	126
Tajweed	25
Arabi	29
Arabi mashq	19
Diniat	118
Urdu Modern	152
Hindi	72
English	64

Mthematics	61
Games	32
Hifzan-e-Sehat	62
Method of Salat	86

Conclusion

From the above table one can easily conclude:-

1. Madrasas are playing a vital role in literacy movement.
2. It is the real foundation of Muslim education in India.
3. Madrasas are gradually tending to include modern subjects
4. It means the people who run these institutions realize about the present day economic and social needs of Indian Muslims.
5. Madrasas can be converted into vehicles for communication of secular and modern knowledge to ensure more Muslim participation in all walks of life.
6. It is possible to empower the entire community through the modernization of Madrasas.

Problems Faced by Madrasas

1. Non availability of qualified teachers for teaching modern subjects
2. Contract Teachers provided by Urdu academy Delhi for Math, Science and computer are not serious and are irregular even they may be absent continuously for two months.
3. No infrastructure is provided by govt. agencies for these subjects.
4. Adequate Teaching Learning Materials on science and Math are not prepared in Urdu.
5. No technical hand for computer operation is provided.
6. No proper method of Evaluation.

Government Intervention: Handle with Care

The central as well as the state government of India provide various facilities to make easy the **Madrassa education in India**. To help Muslim students get higher education, the Central government is trying to permit Madrassa students to join conventional courses in various colleges and universities. In pursuance to the revised POA-1992, two new Central Scheme, i.e., (i) Scheme of Area Intensive programme for Educationally Backward Minorities and (ii) Scheme of Financial Assistance for Modernisation of Madrasa Education, were formulated. Madrasa Modernization is an on going programme under which those Madrasa that volunteer to impart teaching in modern subjects such as Science, Mathematics, English etc, in addition to the traditional religious learning, are assisted through State Governments. National Monitoring Committee for Minorities Education (NMCME) has set up a Committee of Experts on Modernization of Madrasa. The NMCME has suggested toremove weaknesses in the existing Madrasas Modernisation Programme. Based on these suggestions, the programme is being modified to provide for linkage of volunteering Madrasas with the National Institute of Open Schooling (NIOS) and imparting of vocational education in addition to modern subjects, without affecting their traditional teaching.

A Central Monitoring Committee for Minorities Education is also being set up which will monitor implementation of programmes proposed in chapter 3 of POA, 1992.

NCERT has been organising seminars and training programmes for principals/teachers of minority managed schools. The programme include seminar cum-workshop for principals and managers, and

training programmes for teachers from minority managed institutions in subject areas of English, Science Mathematics, Vocationalisation of education and Educational Evaluation. Such training programmes are also being organised by the Regional Resource Centres of NCERT. About 450 Principals and 950 teachers have been trained so far.

Department of education have prepared policy norms and principal for recognition of educational institutions as minority managed institutions and these have been circulated to State Governments for enabling them to prepare detailed guidelines in the matter.

The role of NGOs in Madrasa Education for Democratic Citizenship

* to strengthen their efforts to ensure equal access to quality education for all, including all disadvantaged sectors of society and ethnic, national, social, sexual, cultural, religious and linguistic minorities;
* to express their support for, and profound commitment to Education for Democratic Citizenship, and continue their efforts to make public opinion aware of this vital dimension of democracy;
* to support efforts by NGOs to encourage civic participation and to form effective, well-informed and committed citizens;

References

Encyclopaedia of Islam, New Edition, edited by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs.

Ahmad, Manzoor, Islamic Education: Redefinition of Aims and Methodology, New Delhi: Genuine Publications, 1990.

The Constitution of India – Article 29, 30

R.Upadhyay, MADRASA EDUCATION IN INDIA**-** *Is it to sustain medieval attitude among Muslims?*

NCERT, Self Learning Material for Teacher Educator, vol. I

NCERT, The Reflective Teacher

PRIMARY LEVEL CURRICULUM IN MADRASAS: A STAGE TO IDENTIFY POTENTIALS, NURTURE CREATIVITY AND SET REAL DIRECTION TO LIFE

Dr. Jasim Ahmad
Sr. Asst. Professor
TT&NFE (IASE)
F/O Education, Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

In recent years Madrasas have attracted immense attention, more so than mosques, temples, churches and other endowed institutions of India. The reason behind this is perhaps the general perception of the masses belonging to other faiths that fundamentalism, Islamization and extremist violence stem from the Madrasas. This requires a demand for debate on modernization of Madrasa education and to have a critical overview of all aspects of madrasa education and about its products i.e. passed out individuals of madrasas and their quality of life.

Ever since the emergence of *madrasa education,* it has persisted with a curriculum that has seen a little change. The fact that literally lakhs of Muslim children, especially poor family children, acquire their primary, and perhaps their only formal education, in these *madrasas* where only literature and Islamic studies with a cursory knowledge of social sciences are imparted. This should be a matter of concern not only to their parents but also to anybody concerned with education in any manner. The format of the education imparted to the students of madrasas ought to be modified keeping in view the shifting demands of the employers – a concern which can no longer be under-played. And this is perfectly possible without any kind of erosion of the cultural and religious identity of the madrasas.

Madrasas need to recognize that the world has undergone a transformation in the present age of privatization and globalization. Employers have specialized needs which the current educational set up is unable to meet in madrasas. Now a day, a very dynamic personality with the ability to reflect and create something new is needed in the personality of the individuals-the job seekers. Global and private competition, not to mention financial constraints, is not likely to disappear in the foreseeable future. Forwarding more of what they are currently doing is not the solution to these problems. To survive present and future challenges, the *madrasas* must find new ways to extend contemporary education to their students. This is the age of competition, age of survival of the fittest (Charles Darwin Theory), therefore all educational institutions including madrasa, need to produce the kind of citizen who can face these competition and can prove to be the best or the fittest in changing scenario.

This is the time we require to think the functions of education, which it has been performing since the past and what it requires to perform in current scenario. Education involves transference to others, of **knowledge and values** accumulated by mankind. Even though schools and teachers have been part of the process of education for hundreds or even thousands of years, it is the **spirit of enquiry** that has enriched mankind with knowledge. We learn through reading, listening, watching others, saying, doing and other experiences, and by observing the world in general.

While analyzing the present curriculum and functioning of madrasas, we need to find the answer to the following important questions:

1. Do the managing committee of madrasa lack clarity of vision about the present day economic and social needs of Indian Muslims? Do they have clear cut vision about the future of madrasa and its products?
2. Are they playing a positive role in the scheme of their education?
3. Can Madrasas be converted into vehicles for communication of secular and modern knowledge so that Muslim participation in civil society increases?
4. Do the products of madrasas leading a satisfactory level of quality life?
5. Is it possible to empower the entire community through the modernization of Madrasas?

The functions of education in the present scenario can be seen in the light of the expectation of the stakeholders of education at various levels of education: primary, elementary, secondary, sr. secondary and higher education. The expectations at all stages are interlinked and the expectation at higher level cannot be achieved until a required level of it is achieved at lower levels.

Inculcating a spirit of scientific enquiry in students will perhaps be the best manner of propelling them on the path of learning. In this context it becomes necessary to stress that science and mathematics education, coupled with modern technology, if put to proper use in *madrasas*, could probably make education more meaningful. In modern times, there has been a paradigm shift in the business of education from 'teaching' to 'learning'. It is a demonstrated fact that much learning can happen if the student is left to himself in the proper environment, with the proper resources, tools, and most of all, with proper guidance. Fundamental changes in the educational system may be possible, and indeed essential.

Teaching modern subjects like science, mathematics, computers etc opens the mind, blooms the personality of the child by making them logical, creative, reflective, analytical and rational which are the most important attributes of personality to grow and develop in modern era of development and privatization.

When we discuss and debate upon the subject of madrasa education and the need for reorientation of such institutions according to contemporary advances in the field of modern education, our memory heats back to that one unique madrasa, the **Madrasatul Uloom**, founded by Syed Ahmad Khan in 1875 at Aligarh, which had a historical and revolutionary role to play in the lives of the Indian Muslims after the Sepoy Mutiny of 1857. Syed Ahmad Khan was painfully conscious of the plight of Indian Muslims who were **blissfully ignorant of the various developments in the field of Western Sciences and philosophy.** Syed Ahmad realized the need of that time – the desperate need of the Muslims to acquire **contemporary education and learn the English language**, **which the conservatives resisted as the language spoken by the 'mushriks'**. He launched, with a missionary zeal, to establish a madrasa, a school where the Indian Muslim youth would receive definite guidelines about their future. Keeping in mind the Islamic concept of 'deen' balanced with 'duniya' he fought all obstacles to achieve his aim – that of establishing an institution which combined the best of both the **Orient and the Occident – religious teaching combined with scientific education**. He vigorously attacked the **social conservatism** which rejected any advance or change and in turn received brickbats for his so-called radical views. According to Syed Ahmad the prime requisite of the Indian Muslims at that time was the acquisition of knowledge not only of Islamic thought but also of logic and natural philosophy and he firmly believed that there was no

conflict between Islamic thought and these branches of knowledge. Earlier he had also established the Scientific Society in 1864 at Ghazipur with the purpose of familiarizing the Muslims with Western sciences. The Madrasatul Uloom, for which Syed Ahmad devoted his full life, accepted poisonous and heart pricking comments now stands as one of the most well-known and premier Central Universities of India with international acclaim, attracting students from far and wide. Syed Ahmad's concept of continuity in change paid rich dividends for the Indian Muslims who benefited from this institution, which grew to become the Aligarh Muslim University in 1920. Students who have benefited from this Institution stand proud and distinguished in the world today. The Madrasatul Uloom experiment, which should have served as a paradigm, remains unique even today. Unfortunately not many madrasas followed suit. At the present moment of time, it is needed to bring positive changes in the attitudes of madrasa managing people for transforming the curriculum of madrasa which can produce Islamic Scholars as well as Modern Intellectuals of various fields depending upon their hidden potential so that they can lead a better life by finding better place in various sectors of economy and can contribute in national development.

References:

Ahmad, Manzoor, Islamic Education: Redefinition of Aims and Methodology, New Delhi: Genuine Publications, 1990.

Encyclopaedia of Islam, New Edition, Edited by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs

The Madarsa curriculum: and Demand of the Modern Era

An introduction:

The word *madrasah* is derived from the triconsonantal root د-ر-س (d-r-s), which relates to *learning* or *teaching*, through the *wazn* (form/stem) مفعل(ة) *maf'al(a)*, meaning "a place where X is done." Therefore, *madrasah* literally means "a place where learning/teaching is done. The word is also present as a loanword with the same innocuous meaning in many Arabic-influenced languages, such as: Urdu, Bengali, Hindi, Persian, Turkish, Kurdish, Indonesian, Malay and Bosnian. In the Arabic language, the word مدرسة (madrasah) simply means the same as *school* does in the English language, whether that is private, public or parochial school, as well as for any primary or secondary school whether Muslim, non-Muslim, or secular. Unlike the understanding of the word *school* in British English, the word *madrasah* is like the term *school* in American English, in that it can refer to a university-level or post-graduate school as well. For example, in the Ottoman Empire during the Early Modern Period, Madrasahs had lower schools and specialized schools where the students became known as danismends. The correct Arabic word for a university, however, is جامعة *(jāmia'ah)*.

Being the lifeline of Muslim society madrasa is the real foundation of Muslim education in India.

"Madrasa is an institution of learning, where Islamic sciences including literary and philosophical ones are taught" (Encyclopaedia of Islam - Leiden E.J.Brill). Avowed aim of madrasa education is to inculcate the belief and practice of Islam among its followers and guide them to follow Kuran and traditions of the Prophet.

An important function of the madrasahs is to admit orphans and poor children in order to provide them with education and training. Madrasahs may enroll female students; however, they study separately from the men.

Types of madrasas in India:

Madrasas in India are mainly of two kinds: Some madrasas are affiliated to state governments like in Bihar, Bengal, Jharkhand, Assam, UP and Kerala. Though small, these madrasas draw salaries and collect grants from their respective governments. Thus, the curricula of these madrasas are by and large similar to those of state sponsored schools or colleges in addition to Islamic subjects.

The community based Muslim religious educational institutions are again of four types- (1) Maktab (2) Darul Qura'an (3) Madrasa and (4) Jamia which are institutions corresponding to schools, high schools, colleges and universities in English language. Common people call all these four types of Islamic educational institutions as madrasas. Therefore, our subject of discussion here is the second types of 'madrasa', which are funded and run by Muslims.

Elementary education in Maktabs:

Maktab education provides the primary Islamic knowledge to Muslim children.

Maktabas are usually attached with local *masjids* but many of them function separately. Children up to twelve years of age attend makatabas.
In the medieval Islamic world, an elementary school was known as a *maktab*, which dates back to at least the 10th century. Like madrasas (which referred to higher education), a maktab was often attached to a mosque. In the 11th century, the famous Persian Islamic philosopher, Ibn Sina (known as *Avicenna* in the West), in one of his books, wrote a chapter dealing with the *maktab* entitled "The Role of the Teacher in the Training and Upbringing of Children", as a guide to teachers working at *maktab* schools. He wrote that children can learn better if taught in classes instead of individual tuition from private tutors, and he gave a number of reasons for why this is the case, citing the value of competition and emulation among pupils as well as the usefulness of group discussions and debates. Ibn Sina described the curriculum of a *maktab* school in some detail, describing the curricula for two stages of education in a *maktab* school.

(I) Primary education:
Ibn Sina wrote that children should be sent to a *maktab* school from the age of 6 and be taught primary education until they reach the age of 14. During which time, he wrote that they should be taught the Qur'an, Islamic metaphysics, language, literature, Islamic ethics, and manual skills (which could refer to a variety of practical skills).

(II) Secondary education:
Ibn Sina refers to the secondary education stage of *maktab* schooling as the period of specialization, when pupils should begin to acquire manual skills, regardless of their social status. He writes that children after the age of 14 should be given a choice to choose and specialize in subjects they have an interest in, whether it was reading, manual skills, literature, preaching, medicine, geometry, trade and commerce, craftsmanship, or any other subject or profession they would be interested in pursuing for a future career. He wrote that this was a transitional stage and that there needs to be flexibility regarding the age in which pupils graduate, as the student's emotional development and chosen subjects need to be taken into account.

Curricula of madrasas in India:

A Madrasa usually offers two courses of study: a *Hifz* course; that is memorisation of the Qur'an (the person who commits the entire Qur'an to memory is called a hafiz); and an *'Alim* course leading the candidate to become an accepted scholar in the community. A regular curriculum includes courses in Arabic, Tafsir (Qur'anic interpretation), shari'ah (Islamic law), Hadith (recorded sayings and deeds of Prophet Muhammad), Mantiq (logic), and History of Islam. In the Ottoman Empire, during the Early Modern Period, the learning of the Hadith was introduced by Suleyman. Depending on the educational demands, some madrasahs also offer additional advanced courses in Arabic literature, English and other foreign languages, as well as science and world history. Ottoman madrasahs along with religious teachings also taught "styles of writing, grammar, syntax, poetry, composition, natural sciences, political sciences, and etiquette.

It is impossible to make any general statement about present curriculum of madrasas, as some institutions follow their own pattern. However there are some famous Islamic institutions and Madrasas who have a model curriculum and most of the remaining non-governmental madrasas in India are, some how or the other, affiliated with them or following their system and curricula, like

Darul Uloom Deoband, Darul Uloom Nadwatul Ulama Lucknow, Jamiatul Hidaya at Jaipur, Jamia Salafia Banaras and Jamia Ashrafia Mubarkpur.

All these madrasas and jamiat have a comprehensive syllabus that is based on the pattern of Dars-e-Nizami, but there are some slight differences in the syllabi of these institutions.
Darul Uloom Deoband's present syllabus is for four stages — primary, middle, high and specialization. In the primary (and pre-primary 5 years) syllabi students are taught Urdu, Persian, Hindi, English, Mathematics, Geography, Arabic Grammar and Composition.

Nadwatul Ulama of Lucknow also brought about certain far-reaching changes in the traditional curriculum of the Qaumi Madrasas of India in response to the changed circumstances and needs of the time. The primary five years cover complete primary education as prescribed for general schools besides giving a sound religious base to its students. Higher efficiency in Arabic literature and the knowledge of English equivalent to the Intermediate standard of the U. P. Board of High School and Intermediate Education are the special features of Alimiyat course at Nadwa.

Jamiatul Hidaya at Jaipur: To face and deal with the realities of life and take on the modern challenges, in 1986 a new institution at Jaipur- 'Jamiatul Hidaya' was established. Education in this madrasa begins at the upper primary stage i.e. from class VI and continues for a period of nine years divided into two levels of Sanwi and Aali. The syllabus of Jamiatul Hidaya includes Hindi, English, Social Sciences and intensive technical training besides Islamiyat. In the Jamia the standard of teaching of modern sciences is equivalent to a graduation level course and that of technical education to a certificate level course.

Jamia Salafia Banaras has a unique course for each level from primary upto Fazilah and its syllabus includes English, Hindi, Mathematics, social sciences and some technical training besides giving a particular focus on the teaching of Hadith literature. Jamia Salifia is a model for most of Ahle Hadith madrasas in India, However there are some other Ahle Hadith institutions like Jamia Islamia Sanabil, Delhi, Jamia Mohammadia Male Ganw, Jamia Ibne Taimia, Bihar, etc. who have made some remarkable changes in there syllabi to fulfill the needs of the modern challenges.

Jamia Ashrafia Mubarakpur has also its own curriculum that is followed by the majority of the madrasas and Jamias belonging to Barailavi sect of Muslims in India.

At present all these distinct patterns of curriculum are being followed in the madrasas of the country and each pattern is being separately headed by the institutions mentioned above.

Demerits of Madrasas nowadays:

In this paper I shall try to see why the society and the nation become unable to get maximum benefit from the pass-outs of these educational institutions. Is it that there are loopholes in the system? Why is it that a large numbers of graduates of these madrassas remain unemployed? The increasing numbers of incompetent and unemployment youth passed out of these madrassas and its impact on the socio-economic condition of the region indicates the weakness and loopholes of madrassa education system.

There are deficiencies in the entire madrasa system and the sooner these are looked into and adapted to the changed situation, the better it would be for the community. To name a few of them, for instance:

a. Absence of a centralized agency to exercise control on all madrasas or at least on those within a particular state. Some madrasas follow their own designated syllabus which is a hindrance for smooth functioning and standardising of quality education. All small madrasas should be affiliated to one Jamia or at least a major madrasa of the state and should adopt its syllabus.
b. Lack of modern teaching methodology in about all big madrasas. Every invention is not harmful; thus trying useful new techniques of teachings is a crying need for madrasas.
c. Absence of the ability to cope with the challenges of modern world in its alumni. Meaningful research and discovery have become a thing of past for madrasas. Present Ulama must do things their counterparts have undertaken in the past to meet the challenges of time before it is too late.

In view of this crisis an immediate action plan is necessary to take up remedial steps both from the past success and experiences and contemporary general education. A possible solution could be the incorporation of professional and vocational courses, modern subjects, and modernization of syllabus.

In the absence of modern knowledge the graduates produced by madrasas are neither able to improve their own material prosperity nor they provide leadership to the Muslim community to face the challenge of modern world. Their job opportunity is restricted to mosques and madrasas. Even for higher Islamic studies the degrees awarded by madrasas are not recognised by Indian universities except in the theological department of Aligarh Muslim University and Jamia Millia. Similarly such degrees are not recognised for administrative jobs in the government. Since these degrees are not market friendly, they do not have any practical value.

In view of the on going changes in the social, cultural, economic, and political environment drastic change is required in madrasa system of education so that Indian Muslims could come to terms with the changing needs of contemporary Indian society. The Feeling among the Indian Muslims that government and public schools are loaded with learning related to Hindu culture is to be changed so that Muslim parents could send their children in those schools without hesitation. But the Muslim leaders and thinkers except a couple of exceptions are so much bogged down with the political problems of their community that they are not found assertive on their modern educational problem, which is the real issue.

A section of Muslim thinkers are in favour of modernisation of madrasa education and transforming them according to the present day need. But they hardly oppose the radical Islamists, who suggest that " in stead of turning Islamic madrasas into English or modern institutions, the modern educational institutions be made Muslim" (Education and Muslims in India since Independence - Edited by A.W.B.Qadri, 1998, page85).

Educational backwardness of Indian Muslims is a national problem. But so long they do not respond to the remedial measures it is difficult to be resolved. The Country should be ready for

their rescue provided they come forward and make a conscious effort to transform their madrasas into modern educational institutions with Islamic subjects as optional courses.

The final degrees of these madrassas are Alimat and Fazilat respectively. The duration of the course is very long. Students cross the age of around twenty five years to achieve these degrees. After that if one wants to pursue general education he has to take fresh admission in the lower classes in the general education. That makes higher education for a *Qaumi* madrassa student a far fetched dream. It so happens that many students who pass from these madrassas are immediately appointed in the same madrassas without any sort of proper training. This ultimately leaves an impact on the quality of education. These madrassas are run by the community members through charity and donation. Students are also engaged in fund mobilization. Every year students spend more then fifteen days in fund collection.

Most of these *Qaumi* madrassas do not have recreation facility. These madrassas even do not feel the necessity of physical exercise say in the form of sports. Some of them even imposed restrictions on some sports events. As a result the physical and mental growths of students do not happen. The infrastructure or teaching equipments of most of the *Qaumi* madrassas are not sound.

Salary of the teachers of these madrassas is very poor and negligible. As a result good quality teaching can't be expected in these madrassas because teachers have to look after other options for a stable financial position, which obviously disturbs their concentration in teaching. Again, the subjects like Mathematics, History or English are no way part of the *Qaumi* madrassa education system. Lack of knowledge on these areas makes students of these *Qaumi* madrassas ignorant about the day to day happenings in the world, besides remaining incompetent in the present worlds of professional excellence.

Most of the students of these madrassas especially in *Qaumi* ones are from financially weak Muslims families which is a common phenomenon across South Asia because most of the madrassas provide free lodging and food to its students. So poor parents feel it is convenient to send their children to *Qaumi* madrassas which at least can mitigate some burden from their shoulders.

According to the recent statistics, the number of children going to madrassas is only four percent. So some people think that it does not have much impact on the overall literacy of the Muslim community. They believe that the percentage of Muslim kid drop out from school is far higher than those going to madrassa. It is true that majority of children neither go to school nor madrassa. But one should forget that the madrassa students have immense influence in the Muslim community. Their positive role is very crucial both for the construction of community and the nation. So a proper analysis of the loopholes and drawbacks of madrassa education is crucial for the future of Muslim community in particular and the nation or society in general. Every year students who pass out from different madrassas after getting the highest degrees like *Alimiat*, M.M.., etc have very few opportunities to adjust themselves in the present competitive world. Most of them have to either settle in a local masjid as *Imam* or teacher in madrassas. Only few students dare to enter in the independent business endeavours.

Solutions:

- It is an undeniable fact that from the point of view of what the aims and objectives of a proper madrasa syllabus should be, the majority of texts currently used in the madrasas deserve to be re-looked at. Many of them can be removed from the list of prescribed books that are part of the syllabus and, instead, be made for the students to read on their own.

- Hence, madrasas must be mindful of contemporary conditions, needs and demands and keep the torch of the knowledge of the Faith burning in the light of all these factors. This, in fact, was the aim behind the founding of one of the first and, in many senses, unique madrasas in India following the collapse of Muslim rule in the country.
- The madrasa pass-outs must keep themselves in harmony with the changing needs and conditions of the times. They must seek to answer the new problems that the new times produce and to effectively face new challenges.
- Madrasas must provide their students with knowledge of contemporary developments so as to enable them to understand the objections against and criticisms of Islam and to effectively respond to them. Further, they must also train and inspire their students to effectively communicate the truths of Islam to others.

- we must examine our madrasa education system and allow for necessary changes. In addition, we must also recognise that the general level of the graduates that the madrasas are today churning out is, unfortunately, not very satisfactory, and that their contribution and benefit to society is limited, and, indeed, quite disheartening. Certain aspects of the present system of madrasa education are in need of reform in order to make it more effective and more in accordance with contemporary demands. In this respect one can point to such troubling issues as stagnation in the syllabus, excessive attention being paid to certain subjects and the corresponding lack of adequate attention to certain modern subjects, the focus on mastery of certain specified books rather than certain disciplines, shortcomings in teaching methods, the absence of teaching important languages and the lack of co-ordination and co-operation between various madrasas.

- It is absolutely necessary that books on the history of Islam, of India and of the world be included in the madrasa curriculum.

*A State Level Council for Educational Research and Training in the pattern of NCERT is necessary. Eminent Muslim and non-Muslim Academicians, Senior and experienced prominent Madrassa teachers can be taken as members of the Council. The Council should write and translate books mentioned in the syllabus and publish these books. It should also decide the length of the syllabus at least for the government madrassas and give advice to the state for necessary steps for the enhancement of madrassa education.

*A Central Madrassa Board in the pattern of C.B.S.E is required for the proper conduct of examination and smooth functioning of madrassas. Different types of vocational and professional courses should be introduced at the initiative of central and state governments in the provincialised and community-run madrassas to avoid increasing numbers of unemployment among the madrassa students.

*In this era of latest technology modern teaching instruments/electronic equipments which make teaching easier and understandable for students should be granted to madrassas. The Government,

NGOs, and the madrassa management committees should organize vocational training for existing teachers on different vocational and life skill education.

* At least one Counseling and Guidance centre for madrassa students should open in each district at the initiative of community and government agencies. Councilors of these centers can communicate different options available for madrassa students. Names of madrassa pass outs should also be maintained in the district level employment exchange.

*Since *Qaumi* madrassas are run by different Muslim organisations with different interests, a coordination committee should be set up to maintain good relationship between these madrassas.

The HR ministry of Government of India, has recently declared that a Central Madrasa Board would be setup. This will enhance the education system of Madrasas in India. Though the madrasas impart Quranic education mainly, efforts are on to include Mathematics, Computers and Science in the curriculum.

References:

1. Education and Muslims in India since Independence - Edited by A.W.B.Qadri, 1998, page85).
2. Encyclopaedia of Islam - Leiden E.J.Brill.
3. Gibb, H. A. R. (1970), "The University in the Arab-Moslem World", in Bradby, Edward, *The University Outside Europe: Essays on the Development of University*, Ayer Publishing, pp. 281–298 [281], ISBN 0836915488.
4. Lindsay, James E. (2005), *Daily Life in the Medieval Islamic World*, Greenwood Publishing Group, p. 197, ISBN 0313322708.
5. Goffman, Daniel. *The Ottoman Empire and Early Modern Europe*. United Kingdom: U of Cambridge P, 2002.
6. Qasimi Muahammad Sajid, *Madrassa Education Framework*, Manak Publication, New Delhi, 2005
7. The Milli Gazette Online.
8. Kuldip Kaur: Madrasa: Madrasa Education in India, 1990.

Dr. Naimul Hasan
Sr. Lecturer
Universtiy of Delhi
New Delhi

मुश्किलों के बीच निसाब की यक्सानियत

शकील सिद्दीकी

मदरसों में रायज तालीमी निजाम में प्राइमरी सतह पर निसाब की यक्सानियत या कामन निसाब एक मुष्किल मरहला जरूर है लेकिन किसी भी सूरत में नामुम्किन नहीं। हालांकि इस यक्सानियत से अलग मदरसा तालीम को अस्री तकाजों को पूरा कर सकने लायक बनाना ज्यादा जरूरी है। वह भी उसमें दी जाने वाली मजहबी या दीनी तालीम जिनका एहतिमाम मदरसों के कियाम का बुनियादी मकसद रहा है, रूहानी व इफादी पहलू को बचाए रखते हुए।

मदरसों के तालीमी निसाब में यक्सानियत इसलिए भी जरूरी है कि इसमें तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए यह निजाम फायदेमंद साबित हो सकें। हमें याद रखना चाहिए कि 18वीं सदी में दर्से निजामी की तषकील मदरसा तालीम में यूनिफारमिटी या यक्सानियत लाने और उसे ज्यादा कारामद बनाने के मकसद से हुई थी।

नागुजार हालात में नक्लेमकानी या किन्हीं मजबूरियों के तहत एक इदारे से दूसरे इदारे में जाने की सूरतेहाल को हम जेहन में रखें तो यक्सानियत की इफादियत ज्यादा वाजेह हो जाती है। हम सबके इल्म में है कि अकेले उत्तर प्रदेष में एक साथ कई तालीमी बोर्ड काम कर रहे हैं इनमें सुबाई हुकूमत के जेरे इन्तिजाम काम करने वाले बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0सी0 खासतौर पर काबिले जिक्र है। किसी वजह से एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाने पर बच्चों को किस तरह की दुष्वारियां पेष आती हैं, मुम्किन है हममें से कुछ को इसका तज्रिबा हो। सेन्ट्रल बोर्डों से सूबाई बोर्डों में जाने वाले बच्चों को तो जरियए तालीम बदल जाने से सबसे ज्यादा दुष्वारी पेष आती है। निसाब में जो फर्क होता है वह अपनी जगह पढ़े हुए को फिर से पढ़ना या फिर जिस चीज के बारे में पहले नहीं पढ़ा, उसे नए सिरे से पढ़ना। जाहिर सी बात है, ऊपरी या सेकेन्ड्री सतह की क्लासेज की सतह के मुकाबले प्राइमरी सतह पर इस तरह की दुष्वारियां कम पेष आती हैं। मदरसा तीलाम का यह मजबूत पहलू जरूर है कि कम से कम सूबाई सतह पर प्राइमरी एजूकेषन का जरियाए तालीम एक ही है। मदरसा तालीम में मरकजियत की कमी पर नजर डालें तो मालूम होगा कि इंतिषार का बोलबाला है। मुल्क और सूबे की बात को छोड़िए एक जिले में मुख्तलिफ मदरसों में मुख्तलिफ निसाब रायज है। कहीं दारूल उलूम देवबंद का निसाब है, कहीं नदवतुल उलेमा का, मरकजी मक्तवाएं इस्लामी का, कहीं मजहारूल उलूम का, कहीं तन्लीषी जमाअत का, उत्तर प्रदेष दीनी तालीमी कौंसिल का भी एक निसाब है, जो मुतअदिद मदारिस में रायज है। कहीं सूबाई अरबी फारसी बोर्ड का, कहीं–कहीं तो मुदर्रिस या मोहतमिम खुद तय कर लेते हैं कि क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं। प्राइमरी सतह पर इस तरह के फैसले लेने में खास दुष्वारी पेष नहीं आती। बरेलिवी मसलक का मुदर्रिस सूफी बुजुर्गों के करामात को या उनकी सवानेह को निसाब में षामिल करना समझे। मुम्किन है, कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी हो तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। षिया मदारिस का भी करीब–करीब यही हाल है। हो इन्तिषार की कैफियत इतनी संगीन नहीं है। तो जो अषखास या इदारे निसाब में यक्सानियत की मुहिम चलाए उन्हें अकायद यानी अकीदों में इख्तिलाफ का ख्याल जरूर रखना चाहिए। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर षहरी को यह हक दिया है कि वह अपने अकीदे के हिसाब से मजहबी रूसूमात ओर फरायज तो पूरे करे ही साथ ही तालीम भी हासिल करे।

अब मदारिस में को एजूकेषन का रिवाज आम हो रहा है। यानी लड़के–लड़कियां बहुत जगह एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, प्राइमरी सतह पर यह रिवाज ज्यादा मक्बूल है। इसके बारे में दकियानूसी हज्रात के मन्फी या इख्तिलाफी रवैये में भी पहले जैसी षिद्दत नहीं रह गई है। कामन निसाब बनाने वालों को इस पहलू पर जरूर गौर करना चाहिए कि प्राइमरी सतह पर कुछ ऐसे उलूम हो कसते हैं, लड़कियों के लिए जिनकी रूषनासी जरूरी है। लड़कियों के लिए मकसूस मदारिस के जिम्न में भी इस पहलू पर गौर करना चाहिए। यों तो मेरे ख्याल से लड़के लड़कियों के लिए तालीमी निसाबमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फिर भी लड़कियों में तालीम को मक्बूल बनने के लिए या उन्हें मदारिस की जानिब रागिब करने के लिए कुछ उलूम

को निसाब में षामिल करना जरूरी महसूस होता हो तो उस पर गहरे गौराफिक्र के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।

प्राइमरी सतह पर मदरसों के लिए यक्सां निसाब बनाते हुए इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि निसाब का ढांचा ऐसा बनाया जाए कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे अगर प्राइमरी के बाद दूसरे बोर्डों या गैर मजहबी तालीमी निजाम में जाना चाहें तो उन्हें ज्यादा मुष्किलों का सामना न करना पड़े। हमें यह बात भी जेहन में रखनी चाहिए कि मदारिस के जिम्मेदारान का एतिमाद हासिल किए बिना कामन निसाब रायज करना मुम्किननहीं और जल्दी किसी पर एतिमाद करने वाले नहीं। दीनी तालीमी कौंसिल जिसने मदरसों के निसाब में जरूरी तब्दीली का षुअर तो पैदा ही किया, अपने मदरसे भी कायम किए और मतवाजी निसाब की तषकील भी की। चुनान्चे इस कौन्सिल का ताबुन हासिल करने पर संजीदगी से गौर होना चाहिए।

गुजरात के मदरसों में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम

भारत की 11 पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च षिक्षा को ही केन्द्र में रखा गया था। उसके लिए बजट में 7.7% से बढ़ाकर आज 19% कर दिया है। उसकी वजह से IIM एवं IIT से टैफ्नोफ्रेट और एडमिनिस्ट्रटर पैदा हो रहे हैं। भारत विष्व में आर्थिक सत्ता के रूप में उभर रहा है। भारत में हर साल 25 लाख स्नातक पैदा होते हैं, जो सारे भारतीय युवा वर्ग के 10% है। इसका मतलब यह हुआ कि 90% की षिक्षा का कोई ठिकाना इस देष में नहीं है। सोचने से पता चलता है कि उसके मूल में प्राथमिक षिक्षा की अपर्याप्त सुविधा है। द्वितीय महायुद्ध (1939–45) के बाद रूस, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड आदि खत्म हो चुके थे लेकिन उन्होंने षिक्षा के माध्यम से विषेषकर प्राथमिक षिक्षा पर ध्यान देकर आज की विकासात्मक स्थिति पाई है।

किसी भी समाज, राष्ट्र और समूचे विष्व को यदि सही रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसके प्रमुख साधनों में केवल षिक्षा हो सकती है। इसलिए हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साहब ने भी भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने हेतु अपने ''मिषन 2020'' में प्राथमिक षिक्षा को सृजनात्मक बनाने पर अधिकतम जोर दिया है।

N.C.E.R.T. के पूर्व चेयरमैन डा0 जे0एस0 राजपूत ने ठीक ही कहा है कि "Education has to have its roots in the place, tn the nation and in the culture of country"

गुजरात में N.C.E.R.T. की स्थापना सन 1988 हुई है। तब से लेकर आज तक उसके अंतर्गत चलने वाले गुजरात के करीब 25–26 D.I.E.T. प्राथमिक षिक्षा तालीम एवं संषोधन के तहत सुंदर कार्य कर रहे हैं। NCF-2005 (National Curriculum Framework-2005) की सूचनाओं के मुताबिक N.C.E.R.T. गांधीनगर ने अपना अभ्यास फ्रेम बदल दिया है। जो गुजरात के करीब 38000 प्राथमिक षालाओं में चलता है। गुजरात के मदरसों में N.C.E.R.T. द्वारा प्रमाणित अभ्यासक्रम ही चलता है। उसके लिए कोई अलग अभ्यास फ्रेम नहीं है, गुजरात में मदरसों की संख्या बहुत कम हैं और अभ्यास फ्रेम अच्छा है।

संविधान सभा ने 2002 में 82वें सुझाव सुधार से प्राथमिक षिक्षा को मूलभूत अधिकार का रूप दे दिया, लेकिन परिस्थिति क्या है? भारत की कुल आबादी के 40% निरक्षर हैं यानि कि 1.7 अरब में से 42.80 करोड़ लोग निरक्षर हैं। जिसमें महिलाओं में 54% और पुरूषों में 75% लोग साक्षर हैं। बाकी के लिए हम क्या सोचते हैं।

भारत की प्राथमिक षिक्षा के बारे में 'न्यूया' का सर्वे इस प्रकार है। देष में 11,24,033 प्राथमिक षालाएं कार्य कर रही हैं। उसमें 1,22,355 प्राथमिक षालाओं में 1 षिक्षक है। 21,699 प्राथमिक षालाओं में 1 भी षिक्षक नहीं है। 32,000 प्राथमिक षालाओं में एक भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता। देष की 70% षालाओं में विषय की सुविधा नहीं है। देष की 90 हजार षालाओं में ब्लैकबोर्ड की सुविधा नहीं है।

देष के 6 से 14 आयु वाले सभी बालकों के लिए मुफ्त लाजमी प्राथमिक षिक्षा होते हुए भी 19 करोड़ 4 लाख बच्चे षाला में पढ़ने को जाते ही नहीं। यह भारत के आम समुदाय की बात है। मुस्लिम समुदाय की तो बात ही क्या करें? अल्लाह के महान पैगम्बर मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि ''हर मुस्लिम मर्द और औरत को इल्म सीखना फर्ज अैन है।'' और आगे फरमाया कि ''इल्म सीखने हेतु चीन तक भी जाना चाहिए।'' इतने महत्वपूर्ण आदेष के बावजूद भी हम सोते हैं, कब तक सोयेंगे? यूनेस्को षोध की रिपोर्ट "Learning : the trasure within" में साफ षब्दों में बताया है कि ''सबके लिए समान षिक्षा प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि क्या किया जाए? गुजरात की प्राथमिक षिक्षा के अभ्यास फ्रेम का स्वरूप –

1. मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान होना : सत्य, अहिंसा, षांति, धर्म, प्रेम।

2. ज्ञानेन्द्रियों का समुचित उपयोग करना चाहिए।
3. क्षमतालक्षी, विकेन्द्री एवं आनन्दमयी षिक्षा।
4. बालकों के कक्षा के मुताबिक षिक्षा।
5. षब्द की बजाए स्वानुभव का प्रामाणय।
6. जीवनोपयोगी और गुणवत्तायुक्त षिक्षा।
7. बालकेन्द्री एवं अनावष्यक बोझ से दूर।
8. Learning to Learn की स्थापना

उपर्युक्त सभी मुद्दों को उजागर करने के लिए प्रवृत्तियां

1. अंक की बजाए ग्रेड सिस्टम दाखिल करना जैसे – I.C.S.E., C.B.S.E. में है।
2. बच्चों को प्रयास, प्रयोग, डिस्प्ले जैसी पद्धतियों से पढ़ाना।
3. काउन्सलिंग करना।
4. मां–बाप की मीटिंग साल में दो दफा करना।
5. प्रोफेषनल कोर्स एवं गुणवत्तायुक्त षिक्षण का प्रबंधन करना।
6. तालीमी षिक्षकों की और षिक्षकों की तालीम करना।
7. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, कामर्स पर जोर देना।

डा0 हाजीभाई वडी
लोक भारती, सणोसरा, भावनगर, गुजरात

Participant List for Seminar

S.N.	Name	Address	Mobile No.
1.	Khajan Singh	Beti Foundation C-842, H Road Mahanagar, Lucknow	9838790354
2.	Haji Mohd. Nasirul Haq Ansari	BP/242, Bhittree Peerbatawan, Barabanki	9935844609
3.	Archna Basu	Tauheedul Muslimeen Trust Unity Education Programme Husainabad, Chowk, Lucknow	9415912860
4.	Shilpi Agarwal	SAKAK, Flat No –1, First Floor Galaxy Appartment, Rajendra Nagar, Barelly	9415156296
5.	Dr. Hajibhai Badi	Lokbharti Sanosara Bhawnagar, Gujrat	94269 - 30381
6.	Devendra Mishra	Shashwat Sahbhagi Sansthan Station Road, Misrikh, Sitapur	94155249822
7.	Probir Bose	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9415403679
8.	Anil Kumar Srivastava	Sahara Welfare Foundation Kapoorthala Centre Aliganj, Lucknow	9335226712
9.	Dr. Naimul Hasan	University of Delhi Delhi	9818599781
10.	Shakeel Siddiqui	MIG-317, Phase-2 Tikait Rai LDA Colony Mohaan Road, Lucknow	9839123525
11.	Mohd. Rais	Madarsa Moinul Islam Sundhia Mau, Barabanki	9956782282
12.	Mohd. Quasim Ansari	Madarsa Moinul Islam Sundhia Mau, Barabanki	9450279673
13.	Mohd. Asim Siddiqui	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9453564990
14.	Jameel Ahmad Ansari	M.I.A. Taleemul Quran Mustafabad, Bahraich	
15.	Hafiz Azaz Rasool	Madarsa Shahabul Uloom Shahabpur, Barabanki	9839554224
16.	Ahmad Sayeed	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	
17.	Tarannum Khan	Beti Foundation C-842, H Road Mahanagar, Lucknow	9956399308
18.	Mohd. Moiz Usmani	J.M. Uloom, Rasauli	9919922272

S.N.	Name	Address	Mobile No.
		Barabanki	
19.	A. Razzaque	Madarsa Darul Uloom Barabanki	9336442621
20.	Javed Ahmad Khan	Shakhsaryn, Khairabad, Sitapur	9307047585
21.	Naimuddin Ansari	Moh. Dayra, Biswan, Sitapur	9838151967
22.	Furquan Ali Ansari	Maharajaganj, Biswan, Sitapur	9450820560
23.	Shafique Ahmad Ansari	Sarwagi Tola, Biswan, Sitapur	9307487871
24.	Rejaul Islam	Mahatipur, Chaita 24 pgs(N), West Bengal	9609464997
25.	Abdur Rafeeque	256 B, P.A.S. Road, Kolkata-45	9231664432
26.	Namrata Ghosh	Vikramshila Education Resource Society, 256 B, P.A.S. Road, Kolkata-45	9836233314
27.	Mohd. Suleman	Madarsa Iqra Model School Qaisarganj, Bahraich	9839691379
28.	K.B. Singh	Babbu Wali Gali, Lakar Mandi Daliganj, Lucknow	2740795
29.	Madhumita Halder	Vikramshila Education Resource Society, 256 B, P.A.S. Road, Kolkata-45	9830563383
30.	Ratna Mathur	Sir Dorabji Tata Trust 220 Hans Bhawan, 1 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-02	43508611
31.	Maseehuddin	Mustafabad, Distt.-Bahraich	9889133997
32.	Farrukh R. Khan	OXFAM India, 1 Dalibagh, Butler Palace. Lucknow-226001	9935387786
33.	Prof. S.S.A. Jafri	Giri Institute of Development Study, Sector-O, Lucknow	9335806198
34.	Mohd. Zaim Farooqi	Madarsa Anwarul Quran, Laharpur, Sitapur	9026332986
35.	Mohd. Ehtisham	Madarsa Taleemul Quran, Biswan, Sitapur	9336272220
36.	Tasneem Kausar	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9336509528
37.	Naseem Ahmad	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9984540408
38.	Ziaul Islam	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9307618496
39.	Zeenat Wahid	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9307875700
40.	Farzana Anzum	Madarsa Aminul Kuran, Dariyabad, Barabanki	9936754137
41.	Naheed Aqueel	Prayatna Foundation	9838783837

S.N.	Name	Address	Mobile No.
		B-1396, Indira Nagar Lucknow-16	
42.	Sabir Ali	Furquaniya School, Biswan, Sitapur	9335621491
43.	Mushirul Haq	Dariyabad, Barabanki	9935607098
44.	Sanjeev Srivastava	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9889612808
45.	Pradeep Tiwari	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9889560585
46.	Priyanka Sahu	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9839666605
47.	Aditi Mukherjee	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9839364704
48.	Ashish Awasthi	ANALHAQ	9415470610
49.	Sandeep Manjhi	PROACT, Lucknow	
50.	Mohd. Sabir	Madarsa Rahmaniya, Barabanki	9415917892
51.	Mohd. Amzad	Madarsa Ramania Rahman, Barabanki	9450767556
52.	Ashfak Ansari	Biswan, Sitapur	9452093025
53.	Mohd. Hidayatullah Azmi	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9919622450
54.	Dr. M.H. Quasmi	IASE, JMI, NewDelhi	9818050380
55.	Dr. Jasim Ahmad	IASE, JMI, NewDelhi	9213760821
56.	Jalil Yar Khan Warsi	King Gorge Inter College, Barabanki	9335464341
57.	Murli Lal	PSAUSS, Barabanki	
58.	Prabhat Jha	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9415089316
59.	Tapas Kumar Roy Chowdhary	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9415782696
60.	Deepak Singh Chand	Nalanda B-1/84, Sector-B Aliganj, Lucknow	9415470394